[Prof. Madhu Dandavate]

only idea behind the Bill is to overcome certain difficulties which are there acquiring in the right of user. It is not merely the question of acquiring land. Wherever underground works of railways, as in Calcutta, are going on, the difficulty is that according to the old concept of law and existing legislation, they are mainly concerned with the acquisition of land, and if a particular land-owner owns a particular piece of land, then he enjoys the right of owni'ng the property right from hell to heaven, and wherever we have to take up underground work and dig tunnels, in that case to acquire the users' rights for the subject we are also required to acquire the entire piece of land. And, therefore, this particular legislation

has been brought forward. 4 P.M. There are certain lacunae in

the existing Acquisition Act, 1894 and to remove those lacunae . . . *(Interruptions).*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV). How much time will you take?

PROF. MADHU DANDAVATE: I will take some time. My only idea was that I should hold the floor. Otherwise, I can continue it tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): All right. It will be continued tomorrow.

Now we take up discussion under Rule 176.

DISCUSSION UNDER RULE 176 SITUATION ARISING OUT OF THE HAVOC CAUSED BY FLOODS AND THE CONDITIONS OF DROUGHT PREVAILING IN SOME pARTS OF THE COUNTRY

श्री भीष्म नारायण सिंह (बिहार) : मान्यवर, मैं कृषि मंत्री और कृषि राज्य मंत्री को नहीं देख रहा हूं ।

श्री कल्प नाथ राय (उत्तर प्रदेश) : देश में इतनी बड़ी बाढ़ आयी हुई है और यहां उस पर बहस होने जा रही है और यहां पर सिंचाई मंत्री जी नहीं हैं । . . .

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : लोक सभा में काल अटेंशन मोशन चल रहा है और . . . . . .

श्री भीष्म नारायण सिंह : वह कहीं भी हों । मैं चाहूंगा कि वह यहां आयें । आज देश में करोड़ों व्यक्ति बाढ़ से पीड़ित हैं । पहले से ही राज्य मंत्री जी को कहा जा चुका है कि इस विषय पर बहस होनी है और न यहां कृषि मंत्री उपस्थित हैं और न कृषि राज्य मंत्री ही हैं । इतनी भारी विपदा है और उस से करोड़ों लोग एफेक्टेड हैं. . .

डा० राम कृपाल सिंह : वहां काल अटेंशन खत्म होने जा रहा है और वे यहां आ रहे हैं ।

विपक्ष के नेता (श्री कमलापति त्रिपाठी): मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस समय मंत्री जी का यहां न रहना सदन का अपमान है । इतना बड़ा प्रश्न पेश है और उस के लिये चार बजे का टाइम फिक्स है । ऐसी बाढ़ आयी हुई है वह चाहे बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में हो या महाराष्ट्र में हो, वहां बाढ़ आयी है और लोग उस से पीड़ित हैं और यहां बहस के समय मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं । आप कृपा कर उन को बुलाइये । यह सदन का अपमान है ।

डा० राम कृपाल सिंह: सदन का अपमान करने का कोई मंशा नहीं है । लोक सभा में काल अटेंशन मोशन शुरू हो गया है और उस में थोड़ा समय ज्यादा लग गया है । मैं यहां पर उपस्थित हूं । जो भी प्वाइंट आप उठायेंगे वह मैं उन को पास कर दूंगा ।

श्री कल्प नाथ राय : यह सदन का इतना बड़ा अपमान है। उन को यहां आना चाहिए ।

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal); Sir, if the Minister does not come, I will appeal to the Chair to adjourn the House. And let the Minister be reprimanded for his irresponsibility. You will recall that when we were in the Government, even if we were late by a fraction of a second, we had to apologize for that to the Chair, and many times the Chair pulled up the Ministers and reprimanded them for negligence to their duty. No duty of a Minister can be more responsible and more important than attending the" House. Therefore, let the House be adjourned until the Minister comes. The Minister for Parliamentary Affairs has no business ■to deal with it. He can at best pass on the information, but let the Minister come. He can do one service to the House if he sends a message to the Minister to come immediately. Unless the Minister comes, no business can be transacted.

श्री कल्प नाथ राय : अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री इतने निकम्मे तरह के कृषि मंत्री और बाढ़ मंत्री हैं कि वह पूरे सदन का दिन रात अपमान करते रहते हैं । यह सरकार का एक तरह से दिवालियापन हो गया है। इतनी बड़ी भयंकर बाढ़ उत्तर प्रदेश , बिहार और आसाम में आयी हुई है और करोड़ों लोग उस से बर्बाद हो गये हैं लेकिन उस पर बहस होने के समय कोई मंत्री यहां पर मौजूद नहीं रहता है । अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को डिस्मिस करना चाहिए और आप को इस हाऊस को एडजर्न करना चाहिए । यह सदन का अपमान है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI - SHYAM LAL YADAV): One by one.

सदन के नेता (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मुझे खेद है कि जिन का विषय था वह संबंधित मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं हैं । पता चला है कि उधर काल अटेंशन मोशन चल रहा है । मैंने संदेश भिजवाया है और वह जल्दी ही आ जायेंगे । मुझे इस बात का खेद है कि वे यहां उपस्थित नहीं हैं ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : माननीय सुरजीत सिंह जी या भानु प्रताप सिंह दोनों में से कोई यहां नहीं आ सकते हैं ?

डा० राम कृपाल सिंह : सुरजीत सिंह जी देश के बाहर हैं ।

SHRI PRANAB MUKHERJEE; Sir, no business of the House can be transacted in the absence of the Minister. No other Minister is competent to take care of it.

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव): कृपया स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री कल्प नाथ राय : हाउस को एडजर्न कीजिए ।

श्री नत्थी सिंह (राजस्थान) : मेरा इस संबंध में निवेदन है कि विरोधी पक्ष के कई माननीय सदस्यों की यह बात सही है कि जिस मंत्री का यह विषय है उन को यहां रहना चाहिए । उन की प्रेजेंस यहां आवश्यक है, लेकिन मैं उन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह विषय इतना गंभीर है कि वे इरादतन यहां पर गैर-हाजिर नहीं हैं । दूसरे सदन में काल अटेंशन चल रहा है । इसलिये आप हाउस को एडजर्न न करें और इस विषय पर चर्चा शुरू करें । जो राज्य कृषि मंत्री हैं उन को यहां बुलाया जाय. लेकिन इस विवाद को एडजर्न न किया जाय । इस विषय पर बहस होनी चाहिए ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : श्रीमन् , मेरा सुझाव है कि हम चर्चा आरम्भ करें तब तक राज्य मंत्री जो दूसरे सदन में कालिंग अटेंशन को डील कर रहे हैं वह आ जायेंगे ।

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

दूसरे जो प्रमुख कबिनेट मंत्री हैं वह देश में नहीं हैं . . .

श्री कल्प नाथ राय : देश में बाढ़ आई हुई है वह देश में क्यों नहीं हैं ? निकाल बाहर किया जाए इनको । . . .

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : श्रीमन् मैंने पहले ही सूचित किया कि दोनों यहां पर अनुपस्थित हैं इसलिए मैंने सरकार की ओर से खेद व्यक्त किया । सदन की कार्यवाही ठीक तरह से चले इसलिये मैंने फिर से दोहराया कि यह जो महत्वपूर्ण विषय है फ्लड्स का उसकी चर्चा को रोक नहीं, फ्लड की चर्चा चले । हम यहां पर उपस्थित हैं, हम नोट्स लेंगे, थोड़ी देर में वह यहां पर उपस्थित हो जायेंगे और उत्तर दे सकेंगे ।

SHRI LAKSHMANA MAHAPAT-RO (Orissa): Sir, you -*will* agree with us that there is a definite difference between the concerned Minister hearing and a Minister other than the concerned Minister who is to reply, taking notes and passing them to the concerned Minister. When we speak, we speak in such a way **that** he understands us. He will also be tempted to reply. But passing of notes has some difficulties. It may be that the Minister taking notes does not realise the importance of a particular matter that we speak, that it may not be taken note of and that it may not be transmitted also. These difficulties are there. Therefore, my request to you is this. We are not going away. We do not want the business to be held over to some other date. We will take it up today. Let him come. Now he has come. You can now start.

SHRI DINESH GOSWAMI (Assam): I am raising an important matter of propriety. The notices are given sufficiently i_n advance. I think, in fixing the date for the discussion, the Leader of the $Hous_e$ must have consultation with the Minister concerned also. How is it that a date has been fixed when the Hon. Minister is out of this country? I want to know this because it is not a thing which has been fixed yesterday. I can understand it if today a certain subject i_s fixed for being discussed tomorrow.

SHRI LAL K. ADVANI: It i_s *so* obvious. After all the Minister of State is here. It so happened that the Calling^ Attention motion was taken up in the other House at 3.00 o'clock. Sir, so far as the arrangement of the business is concerned, you will appreciate that normally at 4.00 o'clock the Minister of State lor Agriculture would have been here but for that business.

SHRI DINESH GOSWAMI; That is not my point. My point is different How is it that on a day when the Cabinet Minister is out of this country, thi_s matter has come up for discussion. I can understand it if it happens when in the morning a discussion is fixed for the evening. I can understand it if it happens when today a discussion is fixed for tomorrow and the Minister has already made some scheduled visit. But this is no such type $_0$f discussion. When notices are given sufficiently in advance and dates are fixed in consultation with the Leader and in understanding with the Ministers, I feel that it is irresponsible that a date has been fixed on $_a$ date on which the Minister has gone out of the country. It was his duty probably to inform ^{tn}e Chair that w_e would not be present and' he ought to have said that the discussion should not b_e held on thi_s day, afid the discussion could have bee_n advanced by a day this side or that side. Howsoever the Minister answers to my queries, with all respects I feel that I have my ow_n doubts.

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव) : माननीय सदस्यों की जो भावनाएं हैं वह महसूस की जाती हैं और मैं समझता हूं कि

सरकार का यह कर्तव्य है कि जो सम्बन्धित मंत्री हैं, क्योंकि इस बहस के लिये चार बजे का समय निर्धारित था, उन्हें यथा समय उपस्थित रहना चाहिये लेकिन दूसरे सदन में इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चल रहा था इस कारण, जैसा नेता सदन बता रहे थे कि वह नहीं आ सके, मैं समझता हूं इसका ध्यान सरकार को रखना चाहिये । सरकार को चाहिये कि वह इस प्रकार की व्यवस्था करे कि यहां पर जो समय निर्धारित हो उस समय सम्बन्धित मंत्री उपस्थित हों । जैसा कि दिनेशजी ने बताया कि क्योंकि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और बिजनेस अडवाइजरी कमेटी ने यह समय निर्धारित किया था इसलिये केबिनेट स्तर के मंत्री को यहां उपस्थित रहना चाहिये था ।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: At least the Minister should express his regret that he came late. That is normal courtesy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं थोड़ी सी सफाई पेश करना चाहता हूं । दूसरे संदन में कालिंग अटैंशन 12 बजे था लेकिन लोक सभा के सचिवालय की गलती के कारण वहां के सदस्यों को हमारा वक्तव्य वितरित नहीं हुआ इसलिये उन लोगों ने आपत्ति उठाई और इसके लिये फिर से तीन बजे का समय रखा गया था अन्यथा वह 12 बजे हो जाता और दोनों काम पूरे हो जाते । वहां का कालिंग अटैंशन आगे टल जाने के कारण मुझे वहां थोड़ा समय लग गया । मैंने बहुत कोशिश की कि मैं समय पर पहुंचूं । अगर मैं बीच में ही वहां से उठ कर आता तो वहां के सदस्य रुष्ठ हो जाते । इस असमर्थता के कारण मुझे थोड़ा विलम्ब हुआ ।

श्री रामानन्द यादव (बिहार) : बाढ़ की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसकी हिन्दुस्तान के कतिपय भागों में बहुत चिंता है और सदन भी इसके लिये चिंतित है । ऐसा हुआ है कि सदन में बाढ़ के संबंध में चर्चा के लिये पूरे दिन का समय निर्धारित किया गया लेकिन आज केवल एक घंटा ही हम लोगों को इस पर चर्चा के लिये मिला है . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव): ढ़ाई घंटे का समय रखा गया है ।

श्री रामानन्द यादव: ढ़ाई घंटे में, मैं समझता हूं जितने लोग बोलना चाहेंगे शायद वे नहीं बोल सकेंगे । यह समस्या कुछ लोगों की नहीं है । इस समस्या से बहुत से प्रांत और बहुत से इस सदन के लोग चिंतित हैं और प्रभावित हैं । इसलिये मैं चाहूंगा कि पूरा एक दिन बाढ़ समस्या के संबंध में चर्चा करने के लिये रखा जाए जिससे सभी सदस्य जो बोलना चाहते हैं बहस में सम्मिलित हो सकें । मैं यह नहीं चाहता कि इसको टाला जाए, मैं चाहता हूं कि आज तो ढ़ाई घंटे की बहस हो जाए साथ ही दूसरा दिन भी इस बहस के लिये रखा जाए ताकि सभी सदस्यों को इस बाढ़ समस्या पर बहस करने का मौका मिल सके । आप इस पर सरकार से बात करें और बात करके एक दिन भविष्य में इसी सत्र के अंदर निश्चित करें ताकि बाढ़ के संबंध में हम लोग काफी विस्तार से बहस कर सकें ।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : श्री भीष्म नारायण सिंह जी ।

श्री भीष्म नारायण सिंह: उपसभाध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि बाढ़-सुखाड़ जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जिससे आज देश में करोड़ों लोग पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, उस पर बहस शुरू करने का अवसर मुझे आपने दिया है ।

महोदय, जब भी सदन का वर्षाकालीन सत्र आरम्भ हुआ है लगातार कई वर्षों से किसी न किसी रूप में बाढ़-सुखाड़ की विभीषिका की चर्चा सदन में हुई है । पूरे देश में एक माहौल बन जाता है । बहुत

[श्री भीष्म नारायण सिंह]

थोड़े हिस्सों में अकाल से लाखों, करोड़ों लोग पीड़ित होते हैं और अस्थाई तौर पर इंतजाम की बात कही जाती है या तत्क्षण उनके लिये थोड़ा बहुत सरकार करती होगी लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह समस्या बड़ी मौज है इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या का निदान करने के लिये केन्द्रीय सरकार एक नीति निर्धारण करे। मैं कहना चाहता हूं कि यह बात ठीक हो सकती है कि पहले ऐसा रहा होगा लेकिन यह टैम्परेरी फीचर है। अभी तक सरकार की तरफ से जो भी प्रयत्न किये गये हैं वे सब अस्थायी तौर पर किये गये हैं। आप जानते हैं कि यू० पी०, बिहार, आसाम, राजस्थान, गुजरात आदि स्थानों पर हमारे देश में समय-समय पर बाढ़ हर साल आती रहती है। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में सुखाड़ का प्रकोप भी होता रहता है। इन विभीषिकाओं की रोकथाम के लिए सरकार जो रुपये हर साल खर्च करती है उसके आंकड़े मेरे पास हैं। हमारे देश में बाढ़ और सूखा का प्रकोप एक स्थायी सिलसिला बन गया है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि इन विभीषिकाओं से भारत की करोड़ों जनता की रक्षा करने के लिए कोई स्थायी नीति का निर्माण करे। आप अब तक जिस प्रकार की नीतियों पर चलते रहे हैं उस पर आपको पुनः विचार करने की जरूरत है। यह ठीक है कि यह मामला स्टेटों से संबंधित है और राज्य सरकारें ही फ्लड कंट्रोल का काम करती हैं और केन्द्रीय सरकार केवलमात्र सहायता देती है। वास्तव में देखा जाय तो केन्द्रीय सरकार सहायता क्या देती है, वह तो केवल मात्र बुक लोन देती है। अभी हमारे देश में स्थिति यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता देने के बावजूद बाढ़ और सुखाड़ की विभीषिका बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो इस प्रकार की स्थिति है और दूसरी तरफ कोई नई नीति का निर्माण नहीं होता है। बाढ़ और सुखाड़ से जहां हमारे देश के ग्रामीणों की आर्थिक रीढ़ टूट जाती है वहां राज्य सरकारों की आर्थिक रीढ़ भी टूट जाती है। यह कोई राजनैतिक मामला नहीं है। सभी ओर के सदस्य इस बात से सहमत हैं कि बाढ़ और सुखाड़ के संबंध में केन्द्रीय सरकार को कोई ठोस नीति अपनानी चाहिए जिसमें यह स्पष्ट कहा गया हो कि पांच वर्ष के बाद हमारे देश में बाढ़ और सुखाड़ की विभीषिका से जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। मुझे स्मरण है, माननीय सदस्य श्री पीलू मोदी जी और श्री बिपिनपाल दास जी ने भी यह कहा है कि इस संबंध में इस सदन को कोई डेफिनिट ओपीनियन व्यक्त करना चाहिए और सरकार को कोई स्थायी और ठोस नीति बनानी चाहिए। हमारी राज्य सभा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संस्था है। यह संस्था इन विभीषिकाओं के बारे में सरकार से कोई ठोस और स्थायी नीति अपनाने के लिए कह सकती है। हमारे माननीय राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह जी इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और स्पष्ट शब्दों में कोई ठोस और स्थायी नीति बनायें जिससे भविष्य में इस देश की जनता को बाढ़ और सूखे की विभीषिका से बचाया जा सके। भारत की जनता को इस बात का विश्वास होना चाहिए कि हमारी सरकार अब इन विभीषिकाओं का मुकाबला करने में सक्षम है। अमेरिका के अन्दर इस प्रकार की बाढ़ से बचाने के लिए स्थायी उपाय कर दिये गये हैं। अभी तक हमारे देश में यह स्थिति चल रही है कि सरकार ने इन प्रकोपों से जनता को बचाने के लिए कोई स्थायी योजना नहीं बनाई है। यहां पर हर साल चर्चाएं होती हैं। मेरे पास पिछले 10 वर्ष के आंकड़े हैं, लेकिन मैं उनको दे कर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं कुछ ही वर्षों के आंकड़े दे रहा हूं। सरकार इस बाढ़ और सूखे पर जो खर्च करती है उसके आंकड़े तो उपलब्ध हैं लेकिन जो नुकसान लोगों का होता है उसका मूल्यांकन नहीं नहीं

सकता है । मैं सदन के सामने सिर्फ सन् 1973–74 के आंकड़े रखना चाहता हूं । बाढ़ और सूखे पर इस वर्ष में जो रुपये सरकार ने खर्च किये हैं वे इस प्रकार हैं—आन्ध्र प्रदेश को 1 करोड़ 33 लाख रुपयों का लोन दिया गया, आसाम को 4 करोड़ 75 लाख रुपयों का लोन दिया गया, बिहार को 70 लाख रुपये दिये गये, गुजरात को 33 लाख रुपये दिये गये और जम्मू-कश्मीर को 2 करोड़ 60 लाख रुपये दिये गये । इस तरह से अगर आप इन सारे आंकड़ों को जोड़ें तो आपको पता चलेगा कि यह संख्या अरबों में पहुंच जाती है । फिर आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में साइक्लोन वगैरह आया, वहां गवर्नमेंट को करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ा । दस वर्षों में अरबों-खरबों में इसका आंकड़ा आ गया । More than Rs. 10,000 crores. That is the expenditure incurred by the Government, as a matter of fact.

इसके अलावा आप जानते हैं कि सरकार अपील करती है तो बहुत सारी समाज सेवी संस्थायें उसमें लग जाती हैं । सारी बातें होती हैं । उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझको इसका तजुर्बा नहीं था । मैं उस इलाके से आता हूं जो कि सुखाड़ के लिये मशहूर है । बिहार का बड़ा पिछड़ा जिला एक पठारी इलाका है । लेकिन 1975 में मुझे बाढ़ में घिर जाना पड़ा, तब मुझे इसका तजुर्बा हुआ । नार्थ बिहार के हमारे साथी विधान सभा में जब इसका वर्णन करते थे तो मुझे कभी उनकी बात में संदेह होता था । लेकिन जब मैं बाढ़ में घिरा मैं ही नहीं पूरा पटना शहर घिर गया तब इसकी विभीषिका का मैं अंदाजा लगा पाया । हम सब लोग वहां बाढ़ से घिर गये । मैं मिनिस्टीरियल बंगले में रहता था । गवर्नर हाउस की ड्योढ़ी तक गंगा का जल पहुंच गया था । चीफ मिनिस्टर घिर गये । सारे विधायक घिर गये । सारे शहर में बाढ़ का पानी आ गया । बाढ़ से ऐसी स्थिति बन जाती है कि आप कहीं नहीं जा सकते । इतनी नौकायें भी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हैं और भगदड़ हो जाती है । जो घिर जाते हैं उनके लिये कठिनाई हो जाती है और हफ्तों घिरे रहते हैं । इस तरह की स्थिति बन जाती है । मैंने जब यह देखा तो उस वक्त मेरे दिमाग में यह बात आई कि इसका स्थाई निदान कैसे निकाला जाये । एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई । अगस्त, 1975 में बाढ़ के कारणों और उसकी जांच के लिये उड़ीसा के एक बहुत नामी इंजीनियर त्रिपाठी जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया और कई बड़े इंजिनियरों को उसका सदस्य बनाया गया । मैंने इस समस्या को बड़ा गम्भीर देखा और सोचा कि अगर यह ऐसा ही चलता रहा तो जनता की माली हालत खराब हो जायेगी । राज्य सरकार की माली हालत खराब हो जायेगी और फिर विकास का सारा काम, उत्थान का सारा काम फिर कैसे होगा ? महोदय, जैसे आप जानते हैं कि बिहार राज्य में 75 प्रतिशत से भी अधिक लोगों की आय गरीबी की रेखा से नीचे है । इसलिए मुझे चिन्ता हुई । मैं एक्सपर्ट कमेटी के सामने गया । माननीय श्री भोला पासवान शास्त्री जी यहां पर उपस्थित हैं । वह जब बिहार के मुख्य मंत्री थे तो जहां तक मुझे स्मरण है उस वक्त भी इस तरह की बाढ़ आई थी और यह भय फैल गया कि कहीं पटना शहर में पानी न आ जाये । तो मुख्य मंत्री और गवर्नर सारे लोग दानापुर में जहां नहर टूटी, वहां पर नहर को मजबूत करने के लिये दिन रात प्रयत्न करते रहे थे । यह सब हुआ । डा० जगन्नाथ मिश्र जब मुख्य मंत्री थे तब भी मरम्मत का काम हुआ, तटबंध हुआ, काफी मुस्तैदी दिखाई लेकिन फिर भी वह टूट गया । मैं कहना चाहता हूं कि यह सब जो हो रहा है जो राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार कर रही है यह सब टेम्परेरी बेसिस पर हो

[श्री भीष्म नारायण सिंह]

रहा है । मैं चाहता हूं कि इसका कोई स्थायी निदान निकाला जाये । यह समस्या हमारे देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ रही है । इसलिये सरकार को इसके स्थायी निदान के बारे में सोचना चाहिए । मैं भी एक्सपर्ट कमेटी के सामने अपियर हुआ था । इंजीनियर लोगों से मेरी काफी बहस हुई । मैंने उनको कहा कि पटना को ही आप लीजिये । पटना भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जो कि राजधानी होते हुए भी बाढ़ में डूब गया ।

श्री कमलापति त्रिपाठी : लखनऊ में भी आई थी ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : इससे पहले लखनऊ में भी बाढ़ आई थी, पंडितजी बता रहे हैं । ब्रह्मपुत्र के पानी से आसाम में गोहाटी भी डूब गया था । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस विषय पर आप गम्भीरता से सोचें कि क्या हो सकता है । इस सम्बन्ध में मेरी एक्सपर्ट कमेटी में बात हुई थी और मैंने दो-तीन सुझाव दिये थे । ये डाक्युमेन्ट मेरे पास हैं और यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इसको दे सकता हूं । जब मैं अपियर हुआ तो मैंने कहा कि इसका इस आधार पर निदान होना चाहिए । रेडियो ऐसा यंत्र है जिससे लोगों को समाचार मिलते थे । जब पटना रेडियो स्टेशन भी डूब गया तो उससे भी लोगों को जानकारी प्राप्त नहीं हुई । लेकिन बाद में रेडियो स्टेशन से किसी तरह से कहीं से रिले होकर समाचार मिला करता था । तो रेडियो यह कहता है कि रिहन्द डाम काफी मजबूत है और पानी वहां रोका गया है । रिहन्द का पानी सोन नदी में आया करता है और पटना के पास गंगा नदी में सोन नदी मिलती है ।

पटना प्रभावित होने लगता है । पुन पुन नदी में जब बाढ़ आएगी तो फिर पटना प्रभावित होने लगेगा । तो यह जो सारी नदियां हैं इनका जो कैचमेंट एरिया है जैसे ओरंगा, तहले, कनहर और अमानत सोन की सहायक नदियां हैं और यह सारी बड़ी-बड़ी नदियां सोन में आ कर मिलती हैं । जब तक कैचमेंट एरिया में बाढ़ के पानी को *नहीं रोकेंगे, इसे माडरेट नहीं करेंगे तब तक* बाढ़ नहीं रुक सकती । डा० मिश्रा ने भी बहुत कोशिश की लेकिन बाढ़ नहीं रुकी । आप उनको कहां तक रोकेंगे । क्योंकि सारा पानी जब चला आता है तो प्रयास होने लगता है । रेडियो पर बार-बार कहते हैं कि पानी आ रहा है । रेहान का पानी जब आता है तो पटना बाढ़ के लिए तो भगवान मालिक है । इसलिए यह अवश्यक है कि पहला काम बाढ़ को मोडरेट करने के लिए होना चाहिए । फ्लड को मोडरेट करने के लिए ऊपर में डैम बनाने चाहिएं । वहीं पर पानी को रोकना चाहिए । जहां तक सम्भव हो सके इसके बाद ट्रेनिंग का सुझाव आता है । अमरीका में जैसे नदियों को ट्रेनिंग होती है वैसे आपको भी रीवर्स की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी । अब राज्य मंत्री जी कहेंगे कि *हमारे पास इतनी धनराशि कहां* से आएगी । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां पर दामोदर वैली कारपोरेशन है जिसे डी० वी० सी० कहते हैं । यह मल्टी परपज काम करती है । आप यह देखें कि उसको एक कारपोरेशन बना दिया गया । कारपोरेशन को रुपया मुहैया होने में कोई दिक्कत नहीं आती है । वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करता है और बड़ी-बड़ी देश-विदेश की संस्थाएं हैं जो फाइनेंस करती हैं । दामोदर वैली कारपोरेशन बनने से बंगाल को ज्यादा लाभ हुआ है और बिहार को भी कुछ फायदा है । इससे बाढ़ रुक जाती है । सिंचाई की व्यवस्था होती है, सुखाड़ से भी बचाव होता है । ज्यादा से ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है । इस तरह से आपको करना पड़ेगा । जितने भी रीवर्स हैं जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, जितनी यह सारी नदियां हैं जिनसे बाढ़ का प्रकोप होता है उनके लिए केन्द्रीय सरकार को निश्चित तौर पर कोई योजना

बनानी पड़ेगी । इस तरह से कोई कारपोरेशन बनाएं जो अलग अलग एरियाज़ को देखे और उनको अधिकार दिया जाए कि उनको इस बात का इंतजाम करना है । मैं आपको एक बात यह भी बता देना चाहता हूं कि मैं एक बार वर्ल्ड बैंक के डिपुटी गवर्नर से मिला था और बातचीत के दौरान मुझे बताया गया कि अगर आप सोन नदी कारपोरेशन जैसी कोई कारपोरेशन बना लें तो ऐसी प्रोजेक्ट को हम प्रायर्टी देते हैं । इससे सभी नदियों के बाढ़ के प्रकोप से जो कि ओरंगा, तहले, कनहर और अमानत नदियों से होता है उससे बचा जा सकता है । वर्ल्ड बैंक के डिपुटी गवर्नर ने यह भी बताया कि वे ट्राइबल बैल्ट एरियाज़ के विकास के लिए, अंडर-डवलप्ड एरियाज़ के विकास के लिए, ड्रिंकिंग वाटर की प्रोब्लम दूर करने के लिए लोन के लिए प्रायर्टी देते हैं । जहां पर कोई हाइडल प्रोजेक्ट बन सकता हो वहां के लिए भी लोन देते हैं । इस तरह से आप देखेंगे कि यह ऐसे उपाय हैं जो आपको पहाड़ी क्षेत्रों में करने चाहिएं । आज कल आप देख रहे हैं कि डिफारस्टेशन जोरों से हो रहा है । श्रीमन्, हम जंगल से आते हैं । जहां कैचमेंट एरिया है, जहां पर पहाड़ हैं वहां से जंगलों को काट दिया जाता है तो जब जोरों से वर्षा होती है तो सायल इरोज़न हो जाता है, सायल इरोज़न हुआ तो रीवर्स में सिल्ट हो जाता है जिससे बाढ़ का खतरा पैदा होता है । उपसभाध्यक्ष महोदय, अब आप गंगा को ले लीजिए । गंगा पहले 47 फुट डीप थी जो 17 फुट रह गई है । सिल्ट आने से इसका असर यह होता है कि पानी का स्तर ऊपर आ जाता है । इसलिए यह आवश्यक है कि बहुत बड़े पैमाने पर भारत सरकार को इस काम को करना पड़ेगा । इसलिए मैं चाहता हूं कि नीति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए । क्योंकि राज्य सरकारों पर वित्तीय संकट का सवाल आ जाता है । इसलिए मैं चाहता हूं कि तमाम जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं सब के साथ एफारेस्टेशन का काम किया जाना चाहिए । जिन नदियों से भारत की जनता बाढ़ के प्रकोप से पीड़ित रहती है उनके कैचमेंट एरियाज़ में जो पहाड़ हैं वहां पर डिफारेस्टेशन नहीं होना चाहिए । यह तो और भी अच्छा होगा यदि नदियों के दोनों किनारे के लोग पेड़ लगाएं जैसे कि सड़क के किनारों पर पेड़ लगाए जाते हैं । इससे मिट्टी का बहाव रुकेगा और बाढ़ की समस्या कम होगी । कम से कम जो कैचमेंट एरियाज़ है वहां के पहाड़ों में एफारस्टेशन किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए, वन लगाए जाएं, वृक्षों को काटने पर अविलम्ब रोक लगाई जाए । हम देखते हैं कि ठेकेदारों को ठेके दे देते हैं, बहाना बनाते हैं कि आदिवासी नहीं मानते हैं ,ग्रामीण नहीं मानते हैं यह सब लेम एक्सक्यूज़ हैं । श्रीमन्, मैं पहाड़ी इलाके से आता हूं । मैं जानता हूं सरकार ठेका देती है और ठेकेदार किस बेरहमी के साथ जंगलों को काटते हैं । जैसे उनको स्कीम दी जाती है वैसे नहीं काटते क्योंकि उनकी प्रोफिटियरिंग टेंडेंसी रहती है, उनका आमदनी का ख्याल रहता है । इसलिए वे बिलकुल बेरहमी के साथ जंगलों को काटते हैं फिर सायल इरोज़न होता है उसके बाद सिल्ट का प्रश्न पैदा हो जाता है । यह दो तीन काम केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में लेने चाहिएं । जहां तक बाढ़ की बात है अगर मैं वह बात नहीं कहूंगा तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा क्योंकि इस बहस को शुरू करने का आधार वही था । 27 तारीख के टाइम्स आफ इंडिया में निकला है । अब यहां पर देखिए फ्लड सिचुएशन इन यू० पी० एण्ड नार्थ बिहार, फ्लड रेस्क्यू । यह गोंडा इसमें जब पढ़ा, मैं सदन का वक्त जाया नहीं करूंगा लेकिन इसमें देखें कलेक्टर ने प्राम्पट एक्शन नहीं लिया, आर्मी को नहीं बुलाया नतीजा यह हुआ कि फ्लड आपरेशन का काम ठप्प हो गया, जैसा अखबारों से जाहिर होता है । अब देखिए यह ऐसी विभीषिका है जिसमें एक मिनट भी आदमी ढील नहीं कर सकता, एक सैकिंड के लिए भी,

[श्री भीम नारायण सिंह]

फिर देखिए बढ़ी गंडक रोड, 1–6 किलोमीटर का मधुबनी बंध बना था, फिर देखिए फ्लड हिट्स, 60 लैक्स पीपुल इन बिहार। इसी तरह से बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम का बड़ा हिस्सा अब तो राजस्थान की मरुभूमि में भी, दिल्ली के आसपास तो पिछले ही साल आपने देखा, तमाम देश के करोड़ों लोग पीड़ित हैं और उपसभाध्यक्ष महोदय, यह मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस देश की जनता बहुत जागरूक है, यह आप संसद् में चर्चा कर रहे हैं परन्तु सबका ध्यान इधर होगा कि मेरे लिए इस तबाही में यह केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है। इसलिए यह मामूली सवाल नहीं है, सबका ध्यान इस ओर जाता है इसलिए मैं कह रहा था कि केन्द्रीय सरकार को चाहिए, अभी इमीडियेटली मुझ को आप बतायेंगे जब बोलने लगेंगे तो, कि आपने इन क्षेत्रों में कहीं, जहां जहां की चर्चा मैंने की है, कोई सेण्ट्रल टीम भेजी या राज्य सरकार से कोई आपके पास मांग आयी ? बिहार सरकार ने क्या मांग की क्योंकि बिहार की हालत सबसे खराब है, आपके उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या मांग की वह आपकी स्टेट है, आसाम ने क्या मांग की, हमको हालांकि यह मालूम है कि आसाम को आप 6 करोड़ रुपया परमानेंटली देते हैं परन्तु उससे कुछ होता हवाता नहीं है, रुपया भी बरबाद होता है और बाढ़ की विभीषिका भी रह जाती है। दूसरी बात यह बताइये कि कोई केन्द्रीय मन्त्री अभी तक, यह बड़ा अहम सवाल है मुझको जानना चाहिए, बाढ़ग्रस्त इलाकों में जिनकी मैंने चर्चा की, जाकर कोई अपने विचार बनाये या नहीं, अगर बनाये तो क्या। पुनः उपसभाध्यक्ष महोदय, आप मेरी ओर बार बार इशारा कर रहे हैं, वैसे विषय ही कुछ ऐसा है, लेकिन मुझे अपने सन्तोष के लिए कि आज इस पीड़ा में, इस सदन में, हाहाकार में संसद् सदस्यों का भी यह फर्ज है कि सरकार का ध्यान इस विषय पर आकृष्ट करें और यही नहीं बल्कि दबाव डालें कि सरकार ऐसी नीति बनाये, जिस नीति से यह स्पष्ट रूप से कह सके कि पांच साल या 10 साल या इतने दिनों के अन्दर बाढ़ और सुखाड़ की विभीषिका भारतवर्ष की भूमि नहीं रहेगा, भारत की जनता पीड़ित नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव) कृपया समय को ध्यान में रखेंगे और 5–6 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, हम लोग ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हर मौसम में इन्सान को दिक्कत होती है। जाड़े में तमाम आदमी हमारे यहां जाड़े से मर जाते हैं, सर्दी से मर जाते हैं, गर्मियों में लू से मर जाते हैं और बरसात में बाढ़ आ जाती है। यह जो बाढ़ की बात है इसके बारे में हमें पूरा प्रयास करना चाहिए था लेकिन पिछले 30 सालों में कोई बहुत प्रयास इस ओर नहीं हुए हैं और हर साल इसमें बढ़ोत्तरी ही होती जाती है। जो आदमी मरते हैं, जो सम्पत्ति की हानि होती है, नुकसान होता है उसमें कमोवेश थोड़ी बढ़ोत्तरी ही होती जाती है और हमारे देश में बाढ़ से हर साल करीब 210 करोड़ रुपये की क्षति होती है, इतनी बड़ी क्षति होती है और हर साल हजारों की तादाद में आदमी मरते हैं। इसके बारे में अभी तक कोई राष्ट्रीय नीति नहीं तय की गयी है। यह बाढ़ की समस्या किसी प्रदेश की समस्या नहीं है, कभी बाढ़ बिहार में आ जाती है, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी आसाम में, कभी दक्षिण में आ जाती है और इस साल तो बड़े ताज्जुब की बात है कि राजस्थान भी बाढ़ से प्रभावित हो गया है, राजस्थान जिसके बारे में हम लोग सुना करते थे, जब छोटे थे कि वहां पर पानी नहीं बरसता है। तो वहां पर भी बाढ़ की बात आ गयी। यह विषय

इतना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि इसे राज्य सरकारों पर नहीं छोड़ा जा सकता, इस विषय पर कोई राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। हमारे राज्य मन्त्री जी यहां पर मौजूद हैं, मैं यह चाहूंगा कि एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाय और इस विषय को प्रान्तीय सरकारों से हटा कर केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले। और केन्द्र सरकार को अपने हाथ में लेना इसलिये और भी जरूरी है कि इसका निपटारा प्रान्तीय सरकारें नहीं कर सकतीं। एक नदी जिसमें बाढ़ आती है, वह कई प्रान्तों से होकर गुजरती है। मसलन, गंगा नदी है। वह कई प्रान्तों से गजरती है और गंगा नदी से कई प्रान्तों में बाढ़ आती है। तो, इसे यदि प्रान्तीय विषय रखा जायगा तो समस्या का हल नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर ही बात हो सकती है और हल हो सकता है।

यह जो बाढ़ आती है, उसके तीन-चार जरिए हैं। एक तो नदी से बाढ़ आती है और दूसरा बरसात में बहुत जगह पर बाढ़ आ जाती है क्योंकि पानी सड़क की वजह से रुक जाता है, निकल नहीं पाता और बाढ़ आ जाती है। तीसरा कारण जो पिछले कई सालों से सामने आ रहा है, वह कारण है कभी-कभी बांध में दरार पड़ जाने से या टूट जाने से बाढ़ आ जाती है। बांध के टूट जाने से और दरार हो जाने से भी कई जगह बाढ़ आ जाती है और बड़ा नुकसान होता है।

तो, पहली जो नदी की बाढ़ है, उसे तो हम कुदरती कह सकते हैं। लेकिन बांध आदि जो टूट जाते हैं या सड़कों की वजह से पानी रुक जाता है, तो यह इवन्सानी देन कही जा सकती है। इसमें इन्सान की या जो भी एक्सपर्ट हैं, उनकी कमी कही जा सकती है। जैसे, यदि डैम टूटता है, तो उसमें जो मैटीरियल लगना चाहिये था, वह सही नहीं था।

मैं मन्त्री जी से यह मांग करता हूं और चाहूंगा कि जिन बांधों में खराबी हो, जिनमें दरार पड़ जाए, उससे सम्बन्धित जो भी अधिकारी रहे हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए ताकि आगे आगे आने वाली जो योजनाएं हों उसमें कोई गड़बड़ी न हो। उसमें सही सामान लग सके।

इसके अलावा कुछ जगहें तो ऐसी हैं जिनके बारे में निश्चित रहता है कि हर साल बाढ़ आती है और जब यह मालूम है कि इस जगह हर साल बाढ़ आयेगी तो वहां पर बाढ़ रोकने का इन्तजाम क्यों नहीं किया जाता? वहां बाढ़ रोकने का इन्तजाम किया जाना चाहिये, उसकी व्यवस्था सरकार कीड़ हैफ से होनी चाहिये। कानपुर का उदाहरण है। कानपुर में गंगा जी से अक्सर बाढ़ आ जाती है और उन्नाव जिले का बहुत बड़ा हिस्सा उससे प्रभावित होता है। हर साल कई लाख का नुकसान होता है। वहां बाढ़ को रोकने के लिये, कानपुर में पीने के पानी की और बिजली की व्यवस्था के लिये बहुत दिनों से एक योजना पड़ी हुई है गंगा में बैराज लेकिन उस पर अभी तक काम शुरू नहीं किया गया है। अगर यह योजना क्रियान्वित कर दी गई होती तो बहुत सी जगह पर जो लोगों का नुकसान उठाना पड़ता है, उससे लोग प्रभावित नहीं होते। चूंकि उपाध्यक्ष जी ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं, मैं दो-तीन सजैशंज देकर ही अपनी बात समाप्त करता हूं।

पहली बात, जब बाढ़ खत्म हो जाती है, तो उसके बाद जो आफटर इफ़ैक्ट्स जो होते हैं, उनको मीट करने के लिये हमारी सरकार अभी से प्रयत्नशील हो जाए क्योंकि उसके बाद वहां मलेरिया और हैजा फैलता है, तमाम तरह की बीमारियां फैलती हैं। इसके बारे में मन्त्री जी अलग-अलग जगह पर खास आदेश भेज दें। ताकि सुचारू रूप से काम हो सके। इस समय हमारी सरकार ने जो कुछ भी सहायता इस बाढ़ का मुकाबला करने के लिये बड़े अच्छे ढंग से की है, उसके लिये सरकार को बधाई देनी चाहिये। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इसके लिये हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा और खास करके ऐसी योजना बनानी पड़ेगी जिससे कि बाढ़ के प्रकोप से आने वाले दिनों में बचा जा सके।

श्री भोला पासवान शास्त्री (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरा नाम तो नहीं है लेकिन आपने मुझे मौका दिया ...

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : आपने इच्छा प्रगट की, इसलिए ।

श्री भोला पासवान शास्त्री : इच्छा प्रगट इसलिए कि यह जो बाढ़ और सुखाड़ का सवाल है यह बड़ा बीहड़ सवाल है । यह मैं मानता हूं कि भारत सरकार की तरफ से जब जब फलड्स आते हैं या सुखाड़ आता है तो राज्य सरकार को मदद दी गई है । ऐसी बात नहीं कि मदद नहीं दी गई है, ऐसा मैं नहीं कहता, और फिर राज्य सरकारों के भी जो साधन हैं वे भी उसमें लगाए जाते हैं, कोशिश तो होती है और होनी चाहिए जिससे लोगों को, इनसान की तकलीफ से बचाया जाए । बाढ़ से इतनी तकलीफ होती है—मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा—उसको देख कर रुलाई आ जाती है, अच्छे से अच्छे सम्पन्न लोगों तक को कितने बुरे दिन देखने को मिलते हैं जो बच्चों के साथ नाव में घर छोड़ कर चले जाते हैं, उनके धन दौलत की बरबादी होती है ।

मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन चूंकि इस बाढ़ के प्रश्न पर हमारी अनुभूति ती। है इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहूंगा इस वक्त बिहार, आसाम या पूर्वी उत्तर प्रदेश में वहां इतना काम कर दीजिए कि एक्सपर्ट को भेज दीजिए और अपनी आंखों से देखें कि लोगों की क्या हालत है, दवा दारू की, फूडग्रन की । मवेशी हजारों की संख्या में मर जाते हैं । 1971 में फ्लड आया था बिहार में, मैं खुद मिनिस्टर था, नाव लेकर गया था, गांव के गांव में मवेशी मर गए क्योंकि हम घास नहीं पहुंचा सके, तमाम पानी ही पानी भरा हुआ था । हम यहां पर आए, प्राइम मिनिस्टर इन्दिरा गांधी थीं उनसे मिले तब जाकर कुछ वैगन्स हमको मिल पाए और घास पहुंचाई गई । आज 2 बैल की जोड़ी की कीमत इतनी बढ़ गई है कि हमारे यहां का गरीब आदमी खरीद नहीं सकता है । ऐसे वक्त में पहला काम है कि जहां मानवीयता का, मानव की सेवा का सवाल है, वहां सेवा के भाव से देखना चाहिए इस भाव से नहीं देखना चाहिए कि हमारे सरकारी खजाने में इतना है । टैक्निकलिटीज में नहीं पड़ना चाहिए बल्कि इन्सान और मवेशियों की जिन्दगी को बचाने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए । दवादारू जो केन्द्रीय सरकार की तरफ से देना है उसको समय पर पहुंचाना है । मेरा ख्याल है वह देते हैं । कभी कभी ऐसा होता है कि समय से नहीं मिल पाने के कारण मौतें हो जाती हैं, सरकार को यश नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है, बीच में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि उनकी गलती से गलत काम हो जाता है, करोड़ों रुपए की बरबादी हो जाती है । जब मैं वहां पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर था तो एक नेशनल हाइवे बन रहा था और भारत सरकार के एक्सपर्टस भेजे गए; हमने कहा खगड़िया के नजदीक, मानसी के नजदीक यह सड़क रेलवे की उत्तर साइड में बनाइए; उन्होंने कहा, नहीं, दक्षिण की तरफ से बनेगा । बड़ी बहस हुई । आखिर एक्सपर्टस की ओपीनियन मांगी गयी तो 10 बरस बाद गंगा का सरवे लिया गया कि हमारे यहां दस-बीस वर्ष में ज्यादा से ज्यादा पानी इतना इंच जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा । हमने नहीं मानी उसकी बात क्योंकि हम बराबर अपने प्रदेश से पटना आते थे, बराबर गंगा की हालत को देखते थे । एक कामन मैन की हैसियत से जो हमारा अनुभव था उससे हमने कहा फाइल पर हम यह लिख देते हैं लेकिन मैं एग्री नहीं करता हूं पर चूंकि आप आर्थिक विशेषज्ञ हैं, भारत सरकार के हैं और वहां के प्रतिनिधि भी हैं तो ठीक बात है आपकी बात मानते हैं, सड़क बनाइए । इतनी उम्दा सड़क बनी है, आज भी मोटर से चले जाइए तो मालूम पड़ेगा हवाई जहाज से जा रहे हैं । वर्ल्ड बैंक से जो लोन मिला था,

जितना और स्टेट्स को भारतवर्ष में मिला था, हमको भी मिला था और वह रोड जो 100 मील की बनी थी, वरल्ड बैंक की रिपोर्ट में देख लीजिए--सबसे बढ़िया रोड मानी गई है, जो साइंटिफिक ढंग से, एस्पेसिफिकेशन के मुताबिल एरियल रोड है। लेकिन दो या तीन वर्ष बाद वहां जो गंगा का फ्लड आया तो सड़क टूट गई और हर साल--हम फिगर नहीं दे सकते हैं--करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है, बोल्डर लाने में और उसको बचाने में। तो कभी कभी विशेषज्ञों की राय बड़ी भयंकर होती है, वह काम नहीं देती है। ऐसे कितने ही केसेज हैं। इसलिए बाढ़ प्रकृति का प्रकोप है, चाहे आप जितनी भी व्यवस्था कीजिए। मान के चलना पड़ेगा फ्लड आएगा और सुखाड़ भी आएगा। इसलिए इसमें जो भी काम काम करने वाले हों--- आफिसर, इंजीनियर, डाक्टर या अन्य व्यक्ति--जब तक उनमें मिशनरी स्प्रिट नहीं होगी, काम नहीं चलेगा। ऐसे वक्त में इन्सान की तकलीफ को वह दूर करें। उसको देखने से कलेजा फट जाता है कि क्या मनुष्य के जीवन में कभी ऐसी तकलीफ हो सकती है ? जिसने नहीं देखा उसको अनुभव नहीं होगा। ऐसे वक्त में मैं निवेदन करूंगा कि कहने के लिये तो बहुत सी बातें हैं लेकिन कोई परमानेंट इन्तजाम करिये। गवर्नमेंट आफ इण्डिया को इसका कोई परमानेन्ट इन्तजाम करना चाहिए। बराबर स्टेट्स से मांग आती है कि कोई स्थायी बांध होना चाहिए, लेकिन राज्य सरकारें उसका इन्तजाम नहीं कर सकती हैं। जब तक भारत सरकार उन को सहायता नहीं करती है वह कोई परमानेन्ट इन्तजाम नहीं कर सकती हैं। मैं इतने दिन से सुन रहा हूं। जितना पैसा बाढ़ और सुखाड़ के समय में खर्च होता है अगर उसको योजनाबद्ध तरीके से खर्च किया जाय तो कोई परमानेन्ट हल इसका निकल सकता है। हमारे यहां एक से एक बढ़ कर एक्सपर्टस हैं, लेकिन उसका यह और ऐसा इन्तजाम नहीं हो पाता है। हम जानते हैं कि बाढ़ को कण्ट्रोल नहीं किया जा सकता है। वहां तो हालत यह होती है कि चूंकि बाढ़ आ गयी है इसलिये सबसे पहले उसको रोका जाये और फिर उसके बाद किसी स्थायी इन्तजाम करने की बात को सोचा जाय। जब बाढ़ उत्तर जाती है तो सोचते हैं कि अब तो बाढ़ खत्म हो गयी है, आगे फिर कभी देखा जायेगा। जब फिर दुबारा बाढ़ आयी तो फिर जल्दी जल्दी काम होने लगता है। ये इन्सान का स्वभाव है। जब इन्सान की बीमारी ठीक हो जाती है तो उसके बाद कौन उस की चिन्ता करता है। जो विशेषज्ञ हैं उनको बाढ़ का एरिया मालूम है। कहां बाढ़ आती है यह हम को मालूम है, कहां सूखा पड़ता है यह हम को मालूम है। कहां स्मगलिंग होती है, कहां चोरी होती है, कहां डाका पड़ता है यह सब हम को मालूम है। कहां देर से पानी आयेगा, कहां पहले बाढ़ का पानी आयेगा, कहां का क्या इन्तजाम किया जा सकता है यह सब मालूम है, लेकिन उसका कोई स्थायी इन्तजाम नहीं हो पाता उसका कोई स्थायी इन्तजाम करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो यह होता ही रहेगा। अगर आप तुरन्त नहीं करते हैं तो भले ही न करें, लेकिन उसके लिये विचार रखिये। भारतवर्ष में आसाम है, बिहार है, उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, उन सब में हम कोई अन्तर नहीं करते हैं और वह हिस्से बिहार से कुछ कम दुखी नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को आज के युग में दुखी नहीं रहना चाहिए। चूंकि भारत सरकार की निधि बड़ी है और वह ही कोई स्थायी इन्तजाम कर सकती है इसलिये वह अपने विशेषज्ञ लगाये और इसके लिये कोई योजनाबद्ध काम किया जाय ताकि इस बाढ़ का कोई स्थाई प्रबंध हो सके और बार-बार लोगों को जो इस बाढ़ विभीषिका से तकलीफ होती है वह खत्म होजाये। इस वक्त जो फ्लड आया है उसके बारे में भीष्म नारायण सिंह जी ने बहुत सी बातें सही कही हैं। कम से कम वहां के लोगों को यह शिकायत न होने दीजिए कि भारत सरकार की तरफ से किसी तरह की कमी रह गयी और उसकी गलती से लोगों को कहीं तकलीफ हुई। आप यहां दावे के साथ खड़े होकर कहें और

[श्री भोला पासवान शास्त्री]

हमें बतलायें कि हमारी तरफ से कोई कमी काम में नहीं रही । जब आप का यह संकल्प रहेगा और आप चाहेंगे कि हम अपनी तरफ से जो कुछ भी सम्भव होगा वह काम करेंगे तभी आप राज्य सरकारों को कह सकते हैं कि उन की यह गलती होती है, उनकी तरफ से यह कमी रहती है । जब 1975 में फ्लड आया पटना में तो वहां की बात मैं बतला सकता हूं कि वह क्यों हुआ था । मैं उस समय वहां चीफ मिनिस्टर था । वहां से एक स्वर्ण नदी जाती है । वहां से एक टेलीग्राम आया बिहार गवर्नमेंट को कि पानी छूट रहा है और हम उसको बचा नहीं सकते हैं । आप अपने यहां प्रिकाशन लीजिए । यह रिपोर्ट हम लोगों को मिली । यह पक्की बात है और वहां के विशेषज्ञों ने राय दी कि ज्यादा कुछ नहीं होगा । बाढ़ आयेगी लेकिन इस हद तक नहीं आयेगी कि जिससे पटना फ्लडेड हो जाय । और इस पर लोग बैठे रह गये । अगर प्रिकाशन लिया जाता तो शायद यह हालत न होती उस समय । यह मेरी रीडिंग है । उसके चलते जो हम लोगों को तकलीफ हुई उसको रोज हम टेलीविजन पर देखते थे और वहां जाकर भी देखते थे । लोगों को वहां बहुत तकलीफ हुई । नवम्बर और दिसम्बर तक कमरों में वहां पानी भरा रहा जहां जून में भी पानी नहीं देखा गया था । सरकारी सैक्रेटेरियेट में पानी भरा रहा ऐसी बात तो कभी इमैजिन भी नहीं की गयी थी । वैसे गलती एक्सपर्टस से भी होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरों से भी होती है । तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और ऐसे समय में दूसरे कामों को छोड़ कर इस काम में लगना चाहिए । मेरा अनुभव है कि 1971 में जब फ्लड आया था तो मैंने आर्डर दिया चीफ सैक्रेटरी को कि 15 दिन तक सारी फाइलें रख दी जायं और जितने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं और दूसरे अफसर हैं उन सब को 24 घंटे इसी काम में लगा दिया जाय । और वहां का जो कण्ट्रोल आफिस था वहां चौबीसों घंटे आदमी रहता था कि कहां से क्या खबर आयी है और कहां हम को मदद का काम करना चाहिए । इस क्षेत्र में जो काम आर्मी ने और दूसरे वालेंटियरी आर्गेनाइजेशन्स ने किया है उस की मैं दाद देता हूं । आर्मी में खास कर दानापुर के लोगों ने जो काम किया है वह तारीफ के काबिल हैं । वहां लोगों ने अपनी जान पर खेल कर अपने को जोखिम में डाल कर लोगों को बचाया है । पानी में जाकर अपनी जान को जोखिम में डाल कर लोगों को बचाया है । हमारे दिल में आर्म्ड फोर्सेज और वालंटरी आर्गेनाइजेशन्स के लिए बड़ा सम्मान है । उन्होंने समय पर काम किया । सरकारी अफ़सरों ने भी किया । लेकिन ये संस्थायें भी तैयार हैं । नेशनल वालंटियरीफोर्स भी तैयार रहती है । ऐसे प्रकृति के प्रकोप जब हो जाते हैं तो पहला काम होता है कि प्रायोरिटी इसको दी जाए । सारी मशीनरी को गियर-अप किया जाए । पहले इन्तजाम इन्सान की जिन्दगी को बचाया जाए । मवेशी को बचाया जाए । जब मवेशी को बचा लेंगे तो इन्सान में हिम्मत रहेगी तो इन्सान नहीं मरेगा । इसलिये मेरा ऐसे वक्त पर यहां से भी, वहां से भी तैयारी होनी चाहिए इम्मीडिएट दवा दारू, मेडिकल-एड, डाक्टर्स, खास कर अनाज भेजने और जलावन का प्रबन्ध क्योंकि वह भी कच्चा हो जाता है, जलता नहीं, घास तथा चारे का प्रबन्ध होना चाहिए । अंधेरे में सांप काट लेता है। सब कुछ भगवान के भरोसे रहता है ।

हमारे देश में क्या है कि मुझे खुद जानकारी है एक जगह नाव भेजी जो बड़ी जाति के लोग थे उन्होंने हरिजनों को मार कर भगा दिया और खुद अपने परिवारों को लेकर सूखे स्थान पर आ गये । वहां पर चार आदमी डूब गये । तो जो जबरदस्त आदमी होता है उसकी हर जगह चलती है । अफसर लोग नाव पर सूखी सड़क पर लाकर अपने परिवारों को रख दिये । जो हरिजन बस्ती थी वहां से खबर आई कि हम लोगों के इतने आदमी डूब गये, मर गये । खैर स्पेशल नाव का दानापुर के एस० डी० ओ० को कह कर प्रबन्ध किया गया ।

तो प्रकृति का प्रकोप जब होता है तो उसमें रोमांस भी बड़ा है । मनुष्य कितना बौखला जाता है । कितना अनुभव होता है वह सब सीखने जानने लायक है ।

इसलिए ऐसे वक्त पर सब मशीनरी उस काम पर लग जानी चाहिए और इन्सान की हर मदद करनी चाहिए ।

श्री रामानन्द यादव (बिहार) : श्रीमन्, अधिक समय लोगों को मिलना चहिए खास कर बाढ़ की समस्या पर ।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव) : ठीक है, लेकिन समय भी बंधा है । आप बोलिये मुझे आपत्ति नहीं है ।

Mr. Mahapatro, please be brief.

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO (Orissa): Sir. I will be as brief as possible.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): I would like to request the hon. Members that unless they are very very brief, some of the Member$_g$ may not be able to speak at all- Time is limited.

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO: Sir, in this beautiful country of ours where the nature is so bountiful providing us so many rivers, we are not able to harness those rivers properly with the result that every year we have a sorrowful tale of floods taking a big toll of life and doing much more of havoc as far as our crops and other things are concerned. At one time, we take it as sacred Ganga or sacred Saraswati put it becomes a sorrowful Ganga and a sorrowful Brahmputra. That is how we are seeing it. We should avoid it and this can be avoided. At one time whe$_n$ the Britishers were here, they were trying to protect thos$_e$ particular areas which were yielding good revenue to the Government and they were taking flood protection measure. After we got our independence, we just looked to large$_r$ interests of the community and then we thought of doing something and when in 1954 the floods came all **over** th$_e$ country, that was an eye-opener and thereafter we changed our atti tude. Then only we thought as to ho$_w$ best we should take safety measures to reduce the heavy re curring expenditure caused due to these floods, because after the floods, a lot of expenditure is incurred by way of help to th$_e$ people affected by floods. Therefore, we thought **that** we should do something about it. Not only embankments a'nd other things were provided but we wanted to go in for 3-phased flood protection measures. First one was for imme diate implementation, the second one as a short-term measure$_s$ and the third one wa$_s$ $_a$ long-term measure. In the short-term programme we had some embankments and towards **the** long-term programme, we wanted to construct reservoirs. But we have not take$_n$ note of the different places where th$_e$ reservoirs are to be cons tructed because a lot of water flows down and it is not being kept within the banks and it goes out because of heavy silting of river beds. We have not been able to identify those areas. Now, we have the Central Water and Power Comission and we have also the Central Flood Control Board. These ar$_e$ there. I would not say they do not know the problem. They have bee$_n$ working on this. They are very much on this. There have been So many committees $_a$nd commissions appointed both by the Central and the State Governments. Therefore, they have been able to find out the problem. Th$_e$ problem is known. But we d° hot know how to attend to this problem with the result that every year we have bee$_n$ spending more money. I think, as yet, no calculation has been mad$_e$ to (find out how much recurring expenditure has been incurred during the last ten— fifteen years. When we take an. estimate in regard t$_0$ a particular river to find out of what extent it has caused floods, the figures of the last hundred years are taken. Now, the fact that floods have occured in the Thar desert $_0$f Rajasthan shows that this must be something which

[Shri Lakshmana Mahapatro]

■must have been beyond the imagination of even the forecasters of floods. Therefore, this hundred years estimate has not helped us in solving the problem. We have been having floods in spite of the fact that the entire country has been divided into four .zones for the purpose of flood control.

Now, other hon. Members have spoken about the other, zones. Hence, I would be limiting myself only to one zone^ namely, the Central Indian and Deccan zone. There, you will see that we have got big rivers in one State. Two or three of them are inter-State. Now after a long time, we have been able to solve the problem in relation to Subarnargkhau The three States, namely, West Bengal, Bihar and Orissa through which this river passes have been able to resolve the problem. Similarly, in regard to the other rivers, the problems are being solved. Now, Sir, one of the measures undertaken is the construction of dams. The dams have been named. For example, Bhinkund, Salandi and Bengali. Of these only in regard to Eangali, work has j*ust begun. In regard to the other two, work has not yet begin. As you know, Sir, floods occur during the period June-October when the South-West Monsoon is- active. This is only August. We do not know what havoc will be caused during the remaining months. Of course as yet Orissa has not been affected by floods. But every year, Orissa is one of the worst-afflicted States as far as floods are concerned. Every time, the problem comes. But no attention has been paid so far. Therefore, I would say that our efforts should be to prevent soil erosion. The silting of the river beds is not too meagre. Further, these particular projects which have been identified should be taken up and completed soon. This should be in addition to what you give by way of assistance after the people suffer. You will have to look into these things. Now, we are entering the third stage. This is the stage where we have to think o* permanent measures. We should take up works like construction of storage reservoirs and so on. I read the statement of the Minister which he made in the other House this day- Possibly, he feels, that this year, we have not yet reached the level of 1954 floods. According to him, in 1954, 264 lives were lost. This year, up till now, it is only 260. But the non-official estimates put the death toll at a much higher figure. But one thing I am certain. He has not taken into account the number of deaths that occur due to the various diseases that arise in an epidemic form immediately after the floods. He has also not taken into account the number of deaths that occur as a result of biting by snakes and so on that are brought by the floods. This figure possibly has made him very complacent. So far, the only thing that is being provided to the States for meeting this catastrophe is to give them money by way of advance against their Plan allocation. I have been telling Mr. Barnala that these natural calamities like floods are national problems and therefore, they should be treated as such. They should be dealt with by the Centre and funds should be provided by the Centre. I have been pleading this every time. I would again say this. Now, the Minister may say that it is the Finance Commission which lays down the guidelines. He may say that he will do something when the Finance Commission makes some pro posals in this regard. At the moment, the Sixth Finance Commission has said that there is no scope for special assistance. Sir, the whole Contin gency Fundg of the States are getting depleted because of these floods. Sir, my State, Orissa, is a State which is affected by floods, cyclones, tidal bores and so on. I know the miseries of the people who are affected by these natural calamities. I also know the difficulties of the State Government in attending to these affected people. Therefore, I would say that it is not sufficient if you *go* on incurring recurring expenditure, you shall have to incur non-recurring expendi-

0 P.M.

ture also. Therefore, the real prob^m before the Government, the challenge before the Government, is recurring versus non-recurri'ng expenses. I feel the blame has squarely to be put on the shoulders of the Central Government which i_s not as yet attending to this problem of flood control and miseries of th_e people resulting from flood and other 'natural calamities.

Before I sit down, I would like to say that I know it with certainty that many projects have been sent to the Centre for their approval. They are not in relation to any inter-State rivers, but in relation to rivers which flow within th_e State. But these projects have not been cleared. In the morning, while replying to a question the Minister was mentioning about the cumbersome procedure, that it has to go to the Water Commission, to the Technical Advisory Committee aVid to 'many other agencies. I_n the meantime quite a lot of money is lost by way of damage to crops, cattle, etc. Therefore, Sir, unless you short circuit this particular process of attending to these projects which are sent by th_e States, $_{vo}$u will continue to hav_e these problems. Every year $thes_e$ problems are bound to be there and we will be bound to speak about $thes_e$ $problem_s$ every year and some time of the Parliament i^s also lost in discussing these problems. Therefore, it is my request that these problems of flood and other natural calamities should no longer Tbe left to the States, nor should they he attended t_0 by giving some doles. Is it not true that villages after villages have been marooned due to floods? So, what I say, the problem is known, but the attention is wanting.

श्री कल्प नाथ राय : आदरणीय उप-सभाध्यक्ष महोदय, बाढ़ का सवाल हमारे देश में एक राष्ट्रीय सवाल बन गया है और जब तक हमारी सरकार इस सवाल को योजनाबद्ध ढंग से हल नहीं करेगी तब तक यह समस्या हल भी नहीं हो सकती है। मैं माननीय श्री भानु प्रताप सिंह जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस साल जितनी भी बाढ़ आई है उसमें सबसे ज्यादा नुक्सान बस्ती जिले में रहने वाले लोगों का हुआ है। वे भी उसी जिले के रहने वाले हैं। अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार केवल बस्ती जिले में 19 करोड़ रुपयों की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस समस्या को राष्ट्रीय ढंग से हल करने के उपायों पर विचार किया जाना जाहिए। मैं समझता हूं कि जब तक इस सरकार में बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए पोलिटिकल बिल नहीं होगी तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती है।

आप जानते हैं कि आज के युग में पानी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज हमारे देश में स्थिति यह है कि जब दुनिया चांद और सितारों पर पहुंचने की बात कर रही है तब हमारे देश की सरकार बाढ़ जैसी विभीषिका पर भी नियंत्रण नहीं कर पा रही है। मैं समझता हूं कि इसके लिए ठोस और योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाना होगा। हमारे देश में अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती हैं। हिमालय से लेकर गंगा सागर तक जितना भी इलाका है, इसी में गंगा, यमुना और घाघरा आदि नदियां बहती हैं। यह क्षेत्र हमारे देश का सबसे ज्यादा उपजाऊ इलाका है, लेकिन सबसे अधिक दरिद्र भी यही इलाका है। इस इलाके में सबसे ज्यादा पानी है और पानी का ही उपयोग खेती में सबसे अधिक होता है, लेकिन तब भी यह इलाका सबसे ज्यादा गरीब है। जिस देश में पानी की व्यवस्था हो, वह देश क्यों इतना गरीब हो गया है, इस पर हमें गम्भीरता-पूर्वक विचार करने की जरूरत है। पानी से ही खेती होती है और पानी से ही बिजली पैदा होती है।

सारी तरक्की की बुनियाद बिजली है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हिन्दुस्तान की जो सबसे बड़ी नदियों का क्षेत्र है, जो सबसे उपजाऊ इलाका है, उस इलाके से ही गंगा,

यमुना और घाघरा नदियां निकलती हैं और वह इलाका जो हिमालय से लेकर गंगा सागर तक है, वह, हिमालय से लेकर गंगा सागर के बीच का इलाका ही, हिन्दुस्तान का सबसे दरिद्र इलाका क्यों है ? मैं चाहता हूं कि इस सोने रूपी पानी का इस्तेमाल इस गरीब इलाके की गरीबी, बेकारी और भुखमरी को दूर करने के लिए किया जाए । उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे देश की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पर गई थी । उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि उस बाढ़ को रोकने के लिए उनकी सरकार ने नेपाल सरकार से एग्रीमेंट किया था कि हिमालय से निकलने वाली नदी शारदा, हिमालय से निकलने वाली नदी घाघरा, हिमालय से निकलने वाली नदी राप्ती पर भालू बांध योजना का एग्रीमेन्ट नेपाल सरकार से श्रीमती गांधी की सरकार ने किया था । बहुत मेहनत के बाद , बहुत ही दौड़धूप के बाद एक भारतीय डेलीगेशन वहां गया और उसने यह एग्रीमेन्ट किया । फिर शारदा की पंचेश्वरी योजना, घाघरा की करनाली योजना पर एग्रीमेन्ट हुआ और इन तीनों योजनाओं पर उपसभाध्यक्ष महोदय, 12 सौ करोड़ रुपये खर्च होगा । जब तक भालू बांध योजना, करनाली योजना, जलकुंडी योजना और राप्ती की पंचेश्वरी योजना को हम पूरा नहीं करेंगे तब तक बाढ़ की विभीषिका से उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम को हम किसी भी कीमत पर नहीं बचा सकते हैं । उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जिस इलाके में बाढ़ का सबसे अधिक प्रकोप है वहां के हमारे मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह जी है । मैं उनसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम वे इस पंचेश्वरी और भालूबांध योजना के लिए आवश्यक कदम उठायें । राप्ती नदी के कारण सम्पूर्ण बस्ती, बहराइच और गोंडा का इलाका बरबाद हो गया है वहां पचासों मील तक केवल जल ही जल दिखाई दे रहा है, वहां पशु हजारों की संख्या में मर रहे हैं, करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हो रही है, वहां इंसान की कोई जिन्दगी नहीं रह गई है, वहां 150 लोग मर चुके हैं । उस इलाके की सुरक्षा के लिए भालू बांध योजना जिसके लिए नेपाल सरकार से एग्रीमेंट हो चुका है पर आगे काम करने की कृपा करें । प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई और विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब नेपाल गये तो वहां जो संयुक्त विज्ञप्ति निकली उसमें भी करार नामे का जिक्र है कि नेपाल सरकार इस पर एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है लेकिन इन्दिरा जी के प्रयास से उस योजना को स्वीकृति मिली थी । जलकुंडी योजना की स्वीकृति नेपाल सरकार ने नहीं दी क्योंकि इससे सैकडों मील तक उनकी जमीन पानी में डूब जाएगी । इसलिए इसकी स्वी-कृति उन्होंने नहीं दी । भालू बांध योजना और पंचेश्वरी योजना की नेपाल सरकार और भारत सरकार ने स्वीकृति दी थी । उपसभाध्यक्ष महोदय, हाइड्रो-इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम से अगर बांध बनाया जायेगा तो उससे बिजली भी पैदा होगी । जिस तरह भाखड़ा नंगल डाम ने पंजाब और हरियाणा का रेगीस्तान इलाका हराभरा बना दिया है, वैसे ही पंचेश्वरी योजना के पूरा होने के बाद सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश और बिहार का गरीब इलाका हराभरा ही नहीं होगा बल्कि वहां की बिजली की समस्या भी हल हो जायेगी ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, तीसरा निवेदन मुझे यह करना है और साथियों ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है । जो शारदा सहायक योजना पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के जमाने में एशिया की सबसे बड़ी योजना बनी, इसके अन्तर्गत हमारे इलाके की गरीबी को दूर करने के लिए सारे इलाके में नहरों का जाल बिछाया जा रहा है । लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, शारदा सहायक योजना और गंडक योजना के कारण जिन इलाकों में नदियां नहीं है और जिन इलाकों में नहरों का जाल बिछाया जा रहा है, उन इलाकों में अगर एक दिन भी गहरी वर्षा हो जाय तो वहां सारी फसल नष्ट हो जायेगी और वहां बाढ़ आ जायेगी । तो

वहां पर ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है । इसलिए मैं आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ड्रेनेज सिस्टम को भी नहरों के निर्माण के साथ साथ simultaneously the drainage system should also be allowed to be completed. इसलिए नहरों का जाल बिछे इसके साथ-साथ ही ड्रेनेज की व्यवस्था का भी कार्यक्रम होना चाहिए । इंजीनियर और तकनीशियन्स इसके ऊपर विचार करें और इसके ऊपर अपनी राय दें कि दोनों काम किस तरह से साथ साथ चल सकते हैं ।

तो हमें उन इलाकों में जहां कि बाढ़ की नदियां नहीं हैं और अतिवृष्टि के कारण जहां फसलें नष्ट हो जाती हैं वहां हम फसलों की रक्षा कर सकें । मेरा यह भी निवेदन है कि हमारे नेपाल की सरकार से जो तीनों एग्रीमेंट हुए हैं उन तीनों के लिए विश्व-बैंक से हेल्प ली जाये और विश्व बैंक की मदद से करनाली की पंचेश्वरी और भालू बांध योजना को स्वीकृति दिलाई जाये । हम जानते हैं कृषि मंत्री जी को इसमें क्यों दिलचस्पी हो सकती है । यह हमारी खुशकिस्मती है कि भानु प्रताप सिंह जी राज्यमंत्री हैं । जब तक इस सरकार द्वारा इनिशिएटिव लेकर, डाइनेमिक ढंग से पूरी मुसलसल कोशिश नहीं की जाएगी तब तक जो आज हम बहस कर रहे हैं वह अगले साल भी करेंगे, पांच साल बाद भी करेंगे, 10 साल बाद भी करनी पड़ेगी । बाढ़ को कोई रोक नहीं सकता । एक और मेरा निवेदन यह है कि गंगा, घाघरा, राप्ती यह नदियां ऐसी हैं जिनका पानी 40 फुट था जो कि अब 20 फुट रह गया है । इन नदियों की गहराई लगातार पटती चली जा रही है । जब भी कोई बाढ़ आती है तो पानी का जो डेंजर मार्क पहले था, क्योंकि कम पानी भी आया तो डेंजर मार्क क्रास कर जाती है और बाढ़ आ जाती है । इसलिए मैं यह चाहता हूं कि नदियों को गहरा करने की कोई समयबद्ध योजना सरकार की तरफ से बनाई जाए । चौथा निवेदन मेरा यह है कि एक फ्लड कमीशन बनाया जाए । चूंकि यह राज्य सरकारों का विषय है इसलिए राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार दोनों मिल कर बात करें । । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ को रोकने के लिए प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन और एग्रीकलचर मिनिस्ट्री में कोआर्डीनेशन स्थापित किया जाए । अन्तिम निवेदन मुझे यह करना है कि पानी के इस्तेमाल के लिए नेशनल वाटर ग्रिड सिस्टम होना चाहिए । इसके पहले हमारे कृषि मंत्री राव साहब आन्ध्र प्रदेश से थे उन्होंने कहा था कि हिन्दुस्तान में पानी के लिए नेशनल वाटर ग्रिड बनाया जाए । जहां पानी की ज्यादती है जैसे ब्रह्मपुत्र वैली है . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव) : अब कृपया समाप्त कीजिए ।

श्री कल्प नाथ राय : श्रीमन्, यह एक रेलेवेंट प्वाइंट है जिसे इस समस्या पर विचार करने के पूर्व सोचना चाहिए । मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं । मैं सजेशन दे रहा हूं । सम्पूर्ण आसाम और नार्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए ब्रह्मपुत्र नदी एक वरदान बन सकती थी लेकिन अब वह अभिशाप बन गई है । केन्द्रीय सरकार ने ब्रह्मपुत्र वेली प्रोजेक्ट बनाने की बात की थी । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट को सरकार अपने हाथ में ले ले जिससे पानी को इस्तेमाल कर के बाढ़ की विभीषिका से बचा जा सके । राव साहब ने जो सजेशन नेशनल वाटर ग्रिड सिस्टम का दिया था उसी तरह का सिस्टम बनाया जाए । मैं यह कहना चाहता हूं कि हिमालय से गंगा नदी निकलती है । हिमालय से बंगाल तक बाढ़ के पानी को कंट्रोल करने के लिए इस सिस्टम का निर्माण किया जाए, नहरें बनाई जायें । गंगा की जो योजना कावेरी के साथ जोड़ने की है उसको जोड़ने की कोशिश

की जाए। इस पानी के ठीक इस्तेमाल से हम हिन्दुस्तान को दुनिया का सबसे समृद्धशाली और समृद्ध राष्ट्र बना सकते हैं। वाटर कमीशन आफ इंडिया की रिपोर्ट में लिखा है कि हिन्दुस्तान में जितना पानी होता है उसका 10% विकास के लिए इस्तेमाल होता है और 90% पानी का इस्तेमाल हिन्दुस्तान के विकास के लिए नहीं होता है। वाटर कमीशन आफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यदि हिन्दुस्तान के पानी का विकास के लिए, इस्तेमाल किया जाए जिससे सिंचाई की जाए, बिजली पैदा की जाए तो हिन्दुस्तान की समद्धि पचास गुना बढ़ाई जा सकती है।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव) : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री कल्प नाथ राय : अब मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो आंकडे प्रस्तुत किए हैं . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव): आंकड़ों को रहने दीजिए।

(Interruptions)

श्री कल्प नाथ राय : आप जानते हैं कि मैं ऐसा निवेदन कर रहा था कि जो कि अत्यंत आवश्यक है अगर इस पर आप डिस्टर्ब करेंगे तो मैं हर व्यक्ति को डिस्टर्ब करूंगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आखिरी बात *(Interruptions)* अंतिम बात . . .

(Interruptions)

श्री कमलापति त्रिपाठी : खत्म होने दीजिए, खत्म कर रहे हैं, दो मिनट में खत्म हो जाएगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव) : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अगर वे सहयोग नहीं करेंगे तो उन्हीं की पार्टी के दूसरे वक्ता छूट जायेंगे, उनको हम रोक नहीं सकते हैं, इसका आप ध्यान रखें।

श्री कल्प नाथ राय : एक मिनट, उपसभाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह करना है कि सरकार ने जो आंकड़े पेश किये हैं . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव) : अब आप आंकड़ों पर मत जाइये।

श्री कल्प नाथ राय : एक मिनट, ओनली वन मिनट।

यह जो सरकार ने कहा है कि 1975 में 471 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, 1971 में 1131 करोड़ का नुकसान हुआ और इस साल बाढ़ से और भी नुकसान होने की संभावना है तो इससे बढ़िया है कि 700 करोड़ रुपया बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए जो सरकार ने बताया है कि हमने 30 वर्ष में खर्च किया है तो उस खर्च को 12 सौ करोड़ तक करके पंचेश्वरी, करनाली और भालू बांध को सरकार इम्प्लीमेंट कर दे ताकि बाढ़ की विभीषिका से उत्तर प्रदेश और बिहार को हमेशा के लिए बचाया जा सके। धन्यवाद।

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर उपसभाध्यक्ष महोदय, गत सप्ताह में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से बाढ़ के बारे में चर्चा हुई। बाढ़ की विभीषिका पूरे देश में बढ़ती जा रही है। इस संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया था। किन्तु क्रमशः बाढ़ ने इस तरीके से अपनी विनाश लीला प्रारम्भ करदी है कि उसके महत्व को देखकर पुनः यह लगा कि सदन में कुछ समय, 1 घंटे, 2 घंटे समय लेकर इस पर चर्चा की जाए। हमारे कुछ सम्मानित सदस्यों ने यह भी कहा कि यह एक महत्वपूर्ण समस्या है, राष्ट्रीय समस्या है जिसके ऊपर पूरे दिन भर का समय लगना चाहिए। इस बाढ़ के बारे में प्रतिवर्ष इसी प्रकार की चर्चा चलती है यह भी कहा जाता है कि कोई इसका स्थायी हल होना चाहिए। लेकिन बाढ़ समाप्ति के बाद शायद वे स्थायी हल की बातें केवल मात्र कागज पर रह जाती हैं और फिर से जिस तरीके से अब तक चला है उसी प्रकार की प्रक्रिया अपना रहे हैं। श्रीमन्, सिंचाई आयोग ने अपने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं उनके अन्दर, देखने के बाद यह

लगता है कि प्रतिवर्ष 730 व्यक्ति तथा 43 हजार पशु इस बाढ़ के कारण मर जाते हैं। लगभग 45 अरब रुपये मूल्य की चल तथा अचल सम्पत्ति या फसल नष्ट होती है यानी जबरदस्त देश का नुकसान प्रति वर्ष बाढ़ और सूखे के कारण होता है। इसके बावजूद भी जिस तरीके से इसके महत्व को ध्यान में रख कर सरकार को सारी व्यवस्था करनी चाहिए इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। 1951 में तत्कालीन प्रधान मन्त्री मान्यवर, पंडित जी ने इस सम्बन्ध में विचार किया था और उस समय यह बात आयी थी कि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए हमें बड़े बड़े बांधों को बनाना चाहिए। बांध बने लेकिन दुर्भाग्य से 1954 में जिस तरीके से बाढ़ की विभीषिका देश में निर्मित हुई उसके कारण ऐसा लगा कि बांध ही इसका स्थायी हल नहीं हो सकता है और इसलिए केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की उस समय स्थापना हुई। केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड राज्य सरकारों के द्वारा संचालित बाढ़ नियन्त्रण के जो कार्यक्रम होते हैं, उनके साथ मिल कर एक समन्वय स्थापित करते हुए आंकड़े ग्रहण करता है और उसको अपनी रिपोर्ट के अन्तर्गत ले जाता है फिर उसके अनुसार अपने कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का, केन्द्रीय सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के माध्यम से प्रयास करता है। किन्तु हमारे प्रदेश के अन्दर जो भी प्रयास हुए हैं उन प्रयासों के अन्दर जो आंकड़े आये हैं 1974 तक के, उन आंकड़ों के अन्तर्गत यह हमें देखने को मिलता है कि —उसमें अभी राय साहब ने जो कुछ बातें रखीं—जिस तरह से इस महत्वपूर्ण समस्या को हल करने के लिये काम लेना चाहिये था, वह नहीं लिया गया। उसका परिणाम हुआ कि 10 प्रतिशत क्षेत्र का नियन्त्रण ही इस समस्या का समाधान प्राप्त कर सके हैं। मैं इसी बिन्दु की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता था। इसमें 7,375 किलोमीटर लम्बे बांध बनाये गये, 4,600 गांव को ऊंचे स्थान पर लाया गया और 200 नगरों की रक्षा के लिये कच्ची-पक्की दीवारों से सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। यह जो आंकड़े हैं, 10 प्रतिशत क्षेत्र को बचाने की दृष्टि से ही सक्षम रहे हैं। इसलिये मेरा यह कहना है कि यह प्रकोप जबरदस्त बढ़ता जा रहा है। सरकार को इस दिशा में ध्यान देना चाहिये।

मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में ध्यान आकृष्ट करना चाहता था। अभी बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, बहराइच, गोंडा ये जिले इस प्रकार के हैं जो घाघरा और गण्डक की चपेट में हैं, देवरिया और गोरखपुर में गण्डक, घाघरा, बस्ती में बान-गंगा, बूढ़ी रापती, और रोहणी हैं। यह जो नदियां हैं, वे इस प्रकार की हैं कि जब भी बरसात का समय आता है, उस काल में एक ऐसा स्वरूप धारण कर लेती हैं कि लगता है कि समुद्र सा हो गया है। उसका नियंत्रण करने के लिये अभी किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है।

मान्यवर, पंडित जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। गण्डक परियोजना वहां चालू की गई। गण्डक नदी की जो करेंट या धारा है वह इस प्रकार की है कि जिसके बारे में इंजीनियर भी परेशान रहते हैं। कब वह धारा किधर चली जायगी इसके बारे में निश्चित नहीं कहा जा सकता। इसलिये हमेशा कहीं न कहीं से बांध टूटते रहते हैं और सैकड़ों गांव उसमें जलमग्न हो जाते हैं। ऐसी कई नदियां हैं। इन की धारा को नियन्त्रण में करने के लिये विशेष तौर पर बाढ़ नियन्त्रण दल होना चाहिये, उसे पूर्ण रूप से छूट देकर हर प्रकार का अधिकार प्रदान करना चाहिये ताकि वे ठीक प्रकार से व्यवस्था करते रहें। सरकार उसको बराबर मदद करती रहे।

अभी जो तीन-चार दिन के अन्दर अतिवृष्टि हुई उसके कारण भी अभी जबरदस्त बाढ़ आ गई है और उसके परिणामस्वरूप आजमगढ़ में लगभग 169 गांव प्रभावित

हुए और लगभग 63, 523 एकड़ कृषि योग्य जमीन उससे प्रभावित हुई है । इसी तरह से बहराइच जिले में 602 गांव प्रभावित हुए और 3,62,130 एकड़ कृषि योग्य जमीन प्रभावित हुई ।

इसी तरीके से गोरखपुर, बस्ती और देवरिया की दुर्दशा हुई है । देवरिया में जो बिहार का मधुबनी बांध है, टूट रहा है । अभी समाचार-पत्र में आया है कि वह टूट गया है और सारी की सारी पडरोना तहसील, देवरिया और आसपास के सारे इलाके जल-मग्न हो गये हैं। लगभग 30,000 शरणार्थी बिहार से इस जिले में आये हैं उधर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । उत्तर प्रदेश ने कुछ घोषणा की है । लेकिन उसकी योजना अस्थायी है । उसके अन्दर हमारे सिंचाई मन्त्री ने कुछ प्रस्ताव किया है जलाशय निर्माण करने के लिये । लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है ।

मेरा सरकार से आग्रह है कि अभी मुख्य मंत्री ने जो मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार को 50 करोड़ रुपये का सहयोग दिया जाए ताकि कुछ लोगों को राहत दी जा सके, तो मेरा आग्रह है कि सरकार उसकी तुरन्त व्यवस्था करे ।

साथ ही साथ मैं श्री राय साहब की बात की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अगर पंचेश्वरी बांध, करनाली बांध और मारू गांव बांध नेपाल के समझौते के माध्यम से पूर्ण कर लिया गया तो निश्चित रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो बाढ़ के कारण जबरदस्त नुकसान होता है, वह ठीक हो सकेगा । यह अन्तिम बात कह कर मैं कुछ मांग करना चाहता हूं जो तात्कालिक उस क्षेत्र की जनता के लाभ की चीज है । वह यह है कि अभी जो किसानों की जबरदस्त क्षति हुई है, इसके लिये लगान और बाकी की वसूली को स्थगित न करके उनकी पूर्ण रूप से माफी करने की घोषणा कराई जाए ताकि किसान परेशान न हों । साथ ही साथ ड्रेनेज सिस्टम के न होने के कारण गाजीपुर के मोहम्मदाबाद, जमानिया तहसीलों में तबाही आई है । इसलिए वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जाए ।

इस प्रकार अपनी बात को रख कर मैं सरकार का ध्यान इस विषय की ओर दिलाना चाहता हूं ।

SHRI DINESH GOSWAMI: Mr. Vice-Chairman, Sir I think Mr. Bhisa Narain Singh and my other friends who have tabled this- discussion, but I have not been able to approach this discussion with any enthusiasm. It is because year after year when there have been floods we have always discussed about them in both the Houses, the Ministers have given their stock replies, after the discussion the things have remained as they were and we have waited for another to come when the same discussion has taken place, the same suggestions have been made, the same replies have been given and nothing has been done.

Look at this problem, Sir. This problem has affected not only the entire economy of this country, but it has affected more particularly the backward regions of the country. I would not go mto the details of the statistics, but the fact remains that even according to the official statistics 43,000 catties lose their lives, about 1 -million tonnes of foodgrains are lost, about 730 human lives are lost and thousands of crores of rupees are lost every year because of the floods.

I come from a State which has been a perennial victim of this problem. Because of shortage of time, I do not wa'nt to go into the statistics. This problem of floods has crippled the economy of our State, a State in which 90 per cent of the people depend upon agriculture and 70 per cent of the people live below the poverty line. This has affected the entire economy. More so, when the floods come, apart from the other problems which the other States suffer, invariably the only knk of communication

which we have with the rest of the country, a small rail line, gets snapped, with the result that there are acute scarcity and high prices and the traders immediately go for an artificial price rise, and this also affects the entire people of Assam severely. We have another added problem which the other States are not facing in the same way. We aro faci'ng the erosion problem which has already destroyed one of our most important and beautiful city of Dibrugarh, and it has affected a number of other areas.

How do we tackle this problem? I am not saying that money has not been spent. According to an official estimate, up till now 80 crores of rupees have been spent only in Assam and that has been Speht~rnainly for construction of embankments. I will not like to bring in the issue of corruption at this time and what happens really. But even the official figures which are available with the Agriculture Ministry show that out of these embankments on which 80 crores of rupees have been spent up till now, the official estimation given by the State Flood Control Department has said that not even 1 per cent is really safe; 'not even one per cent is up to the standard; only 0.13 per cent of the embankments is of the required standard. The result is that when high floods come-if there are low floods sometimes the embankments help, but every year in Assam we have more than one high flood— there is over-flow, a'nd because of over-flow there is: seepage and there is breach in the embankments resulting in aggravation of the problem instead of its being helped. Unfortunately, Sir, in spite of the fact that year after 'year there have been demands on behalf of the Slate, and even Members like Mr. Kalp Nath Rai have made the same demand that the problem of Assam and in fact that of the entire country, cannot be tackled by the States, no real attention has been given to it.

Sir, the Brahmaputra is a river which has no parallel and the international experts have said times without number that it requires a tremendous amount of financial assistance and a tremendous amount of technical know-how to tackle the problem of Brahmaputra. This river is 2,880 kilometres long with tremendous u'.ider currents and it drains a catchment area of 73,000 sq. kilometers. And its maximum water discharge is an unparalleled 26 lakh cusecs—to be precise, 25.6 lakh cusecs. We were happy to note that the previous Government, after a long-standing public demand, decided in **1974,** to take over the problem of the Brahmaputra and circulate^ bulletins in both the Houses that a Bill known as the Brahmaputra Board Bill would be brought before the two Houses. When comments were asked for from the States, some differences arose on some provisions and before the matter could ultimately be sorted out, the Lok Sabha was dissolved.

Now I put a question to the Minister in this session of the House and I received the following reply:

> "Flood Control forms part of State Sector and, therefore, the initiation, formulation and implementation of flood control schemes is the responsibility of the State Government concerned."

I do not think there can be a more callous attitude, a more callous type of answer than' this. After al*, India is not divided into water-tight compartments and it is not that the Centre has no responsibility to the States. In fact, Sir, the Centre should remember that the financial autonomy of the States, to a great extent, has been curtailed under the Constitution and so the Centre correspondingly has a duty to see that where the States cannot by themselves undertake certain measures to solve their own problems, the Centre has a duty of its own to help them. Maybe, as they say, flood control is a problem of the States. But whose duty is it under the Constitution to protect the lives of the people? This is a subject of the Centre. In fact, sir, after seeing all these callous statements, I feel that

the time has come when both the Houses should demand unanimously that the subjects of floods and droughts should be transferred from the State List to the Union List immediately. This demand should come.

I am also unhappy to note in this context that the State Government has not made any request for financial assistance for relief measures because the answer says:

> "No request for financial assistance for relief measures has been received from the Government of Assam."

I will 'not make the issue of floods a political issue, but I feel that even if there has been no demand from the State Government, it is the duty of the Central Government to give assistance on its own. After all, in that State it is the Janata Party which is in power a'nd you cannot go to the people and say, "Look here, because the State Government **has** not asked for any relief, you are not going to get any relief." Therefore, I feel that this type of a callous attitude to the problem will not take us far.

I would like the Government immediately to introduce the Bill which ultimately could not be introduced in this House. On that day when sup-plementaries were asked, a reply was given to us that the State Government's comment on the Bill has been received by the Central Government. I urge upon the Minister concerned to look into the matter and take necessary measures to bring forward this Bill before the House.

Sir, in this connection I want to State that it is not that the Central Government did 'not initiate any action on the Brahmaputra". *1* know that in 1965. the then Government asked the Chief Engineer of the United States Bureau of Reclamation, Mr. B. P. Bellifort, to investigate into the matter and he gave a report in which he recommended reconnaissance study of the Brahmaputra basin to determine the feasibility of constructing dams. After that report, something was done. Thereafter, another two experts came. Even I know that at one point of time the Australian Government itself showed some initiative and one of their representatives met me after I had raised the matter when I was a Member of the Lok Sabha. I wrote a letter to the Minister in charge of the Department at that time. I think the letter will be in the files. This may be looked into. In 1970, if my information is correct, the matter was taken up by the Central Government as an US-AID scheme but because of the 1971 political developrnehts probably that could not be persued. I urge upon the Central Government that if necessary, they should even go to the U.N. authority and all other international agencies not only to tackle the problem of the Brahmaputra but to tackle the entire problem of the dangerous rivers in this country.

Sir, since you have become impatient, I will take only two minutes more. Lastly, I feel that the Government has been trying to take only *ad hoc* measures. The Minister in charge of floods is looking to one direction and the Minister in charge of power is looking to another direction; and the Minister in charge of irrigation is looking to yet another direction. There should be a comprehensive scheme so that, on the one hand, the flood problem can be solved and, on the other, the excess waters can be used for more constructive purposes like energy and irrigation. You will be surprised to know that in spite of the fact that the State of Assam is a State in which we have the highest quantity of rainfall and floods every year, we suffer from the problem of lack of power today because of which there is no industrialisation and also there is the problem of irrigation. Therefore, I feel that there should be an integrated flood control scheme I do not know what has happened to that

Flood control Commission which the Government appointed two years ago with Mr. Jaisukhlal Hathi as Chairman. What action has been taken? In fact, there also I have come to know that the Commission has been treated with scant respect and most of the States have not replied to the questionnaire. Even my own State also seems to be guilty of that. The Central Government should urge upon the Commission to look into this matter and to submit their report as early as possible. The problem is of a tremendous dimension. We concede that according to the scientific report out. of the total surplus flow in this country which is said to be 1356 million acre feet—an acre feet means the amount of water that is required to submerge one acTe by one foot deep water—only 450 million acre feet is usable and the rest, of "906 million acre feet has to flow i'ru'o the sea. Therefore, we must have a comprehensive project by which this 90C million acre feet of water can do '-o the sea; otherwise, this perennial problem will remain with us. A'nd the 450 million acre feet of water which is usable should be used for purposes of irrigation, for purposes of power and for other purposes. I know that the honourable Minister will give another of his stock replies as is evident from the reply which T have received and ibe replies which he has given in the Lok Sabha. I do admit that there are diffculties. I would urge upon the Minister, for once he ■must make a begi'nning; Tie must have a comprehensive scheme 6T flood control; otherwise, all this talk is useless and year after year the crores and crores of rupees that we are having to spend will only be a wasteful expenditure. I, therefore, hope, . Sir, that a beginning will be made now. Unless a beginning is made now, I feel all this type of discussion is useless, all this talk will end in futility. Therefore, on behalf of the suffering people I urge upon the Government to take concrete measures in this direction. Thank you.

श्री रामानन्द यादव : अध्यक्ष जी, हर साल की तरह इस वर्ष भी इस देश के बहुत से प्रान्तों में भीषण बाढ़ आई हुई है। मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और उड़ीसा बाढ़ प्रभावित हुए हैं।

अध्यक्ष जी यह बाढ़ हर साल इस देश के कुछ प्रान्तों को इस तरह से नष्ट करती है कि लोग तबाह हो जाते हैं और खास करके वह तबका आबादी का जो गरीब होता है, भूमिहीन होता है, छोटा किसान होता है वह और भी तबाह होता है।

अध्यक्ष जी, इस वर्ष बिहार और उसका उत्तरी हिस्सा जिसे उत्तर बिहार कहते हैं जो मुख्यतः कृषि-प्रधान हैं, वहां करीबन 7 जिले इस तरह से बाढ़ से प्रभावित है कि वहां पर जनजीवन बहुत ही कष्टमय है। उत्तर बिहार में पूर्वी चम्पारन, पश्चिमी चम्पारन, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और सहरसा इस तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं जिसकी इन्तिहा नहीं। आपने अखबार में देखा होगा कि कल बिहार असेम्बली में इस पर बहस हुई और सरकार ने एक तरह से बाढ़ को रोकने में और अधिक से अधिक लोगों की सहायता लेने में अपनी असमर्थता प्रकट की। यह कह कर कि वित्तीय हालत अच्छी नहीं है। केन्द्रीय सरकार को इस मामले में मदद करनी चाहिये। बिहार राज्य की तकरीबन 60 लाख आबादी पूरी तरह से बाढ़ से पीड़ित है। मैंने आपको बताया कि सात जिले हैं जिसमें बूढ़ी गण्डक नदी, अधवारा ग्रुप आफ रीवर, बाघमती और दूसरी नदियां हैं अनड्रेंड है जिसके कारण 60 लाख की आबादी आज बाढ़ से पीड़ित है। इस वर्ष जो बाढ़ आई है उसके मुख्यतः दो कारण हैं। कारण ये हैं कि अधिक वर्षा होने के कारण इन नदियों में काफी पानी आ जाता है और उस काफी पानी से क्षति होती है। साथ ही साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि पहले इन नदियों की ताकत थी कि वर्षा का पानी, क्योंकि नदियों की काफी गहराई होती थी, अधिक वर्षा होने पर भी अपने पेट

[श्री रामानन्द यादव]

में रख लेती थी जिसके कारण बाढ़ नहीं आ पाती थी । आज तक बाघमती योजना, बूढ़ी गण्डक योजना और अधवारी ग्रुप आफ रीवर योजना खटाई में पड़ी हुई हैं । आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आज से 10 वर्ष पहले इंजीनियरों के रहने के लिये सीतामढ़ी, अधवारी ग्रुप आफ रीवर को ड्रेन करने के लिये करोड़ों-करोड़ रुपये के घर बनाये गये थे लेकिन वहां कोई इंजीनियर नहीं रहता । आप जानते हैं रुपये जरूर खर्च हो गये और उसके लिये भारत सरकार ने भी अनुदान दिया था लेकिन प्रतिवर्ष बाढ़-विभीषिका आती ही रहती है । लोग उस एरिया में तबाह हैं । उनका जन-जीवन काफी खराब हो गया है बाढ़ की वजह से । आज से दो वर्ष पहले जब भीषण बाढ़ आई थी मैं वहां गया था । मैंने वहां जाकर देखा था कि बाढ़ पीड़ित लोग, गरीब लोग जो बाढ़ से तबाह थे पेड़ों पर बैठे रहते थे, ऊंचे टीलों पर जाकर रहते थे, दोनों तरफ सड़कों के किनारे रहते थे । मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बिहार सरकार लोगों को किसी तरह का रिलीफ देने में असमर्थ है । मैं कोई पार्टी के आधार पर एलीगेशन नहीं लगा रहा हूं । क्योंकि बिहार सरकार ने असमर्थता प्रकट की है इसलिये मैं चाहूंगा कि भारत सरकार जल्द से जल्द बिहार सरकार ने जो अनुदान मांगा है, अपनी वित्तीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अधिक से अधिक तत्काल आर्थिक सहायता देने का कष्ट करें ।

दूसरी बात मैं चाहूंगा कि आप फ्लड कण्ट्रोल सम्बन्धी टीम बनाएं । सुना है कि पटना में जब पीछे बाढ़ आई थी तो भारत सरकार ने एक टीम भेजी थी । उस टीम ने वहां से आकर अपनी एक रिपोर्ट दी थी और उसी के आधार पर आर्थिक सहायता देते थे । लेकिन कभी दीर्घकालीन योजना बाढ़ कण्ट्रोल करने के लिये नहीं बनाई गई । यह भी सुना था कि एक कमीशन बना है जो इस देश में बाढ़ से प्रभावित प्रान्त हैं वहां बाढ़ पर कब्जा करने के लिए एक रिकमेंडेशन देगा । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस कमीशन का क्या हुआ ? क्या वह कमीशन खत्म हो गया ? अगर वह खत्म हो गया तो आप दीर्घकालीन योजना बाढ़ को रोकने के लिये बनाइये । और इस नीयत से एक कमीशन नियुक्त कीजिए । मैं समझता हूं कि तब जाकर आप इस देश में से बाढ़ को रोक सकेंगे ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे बिहार राज्य में बूढ़ी गण्डक योजना लाई गई । जैसा अभी हमारे साथी कल्पनाथ राय जी ने कहा नहर तो बन जाती है लेकिन ड्रेन ठीक से न होने के कारण बाढ़ आती रहती है । अनप्लांड ढंग से नदियों के बांध बांध दिये जाते हैं पानी रोकने के लिये और वर्षा आने पर गांव के गांव तबाह हो जाते हैं । मैं यह बताना चाहता हूं कि पानी का जो प्राकृतिक ड्रेन था वह आज अवरुद्ध हो गया है जिसके कारण यह बाढ़ आती है । इसलिये बाढ़ नियन्त्रण के लिये एक दीर्घकालीन योजना बनाइये । यह ठीक है कि कुछ शोर्ट टर्म लौन या सहायता बिहार, यू० पी० और दूसरी राज्य सरकारों को दी जाती है, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि इस काम के लिए कोई ठोस योजना बनाई जानी चाहिए । हमारे देश में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित तबका खेतिहर मजदूरों और छोटे किसानों का है । बाढ़ के कारण उनकी फसल नष्ट हो जाती है और पशु बह जाते हैं । बाढ़ग्रस्त इलाकों में बाढ़ के हटने के बाद तरह तरह की बीमारियां फैल जाती हैं, अन्न की कमी हो जाती है और जानवरों के लिए चारा भी नहीं रह जाता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन मुद्दों को मद्देनजर रख कर भारत सरकार को बाढ़ग्रस्त इलाकों की प्रान्तीय सरकारों को जल्दी से जल्दी आर्थिक सहायता देनी चाहिए ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके । मैं यह भी चाहता हूं कि आप बाढ़-ग्रस्त प्रान्तों में अपनी एक्सपर्ट टीम भेजें । जो वहां जाकर सम्पूर्ण स्थिति का अध्ययन करे और उसके मुताबिक उन प्रान्तों को आर्थिक सहायता पहुंचाई जाये ।

अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी बाढ़ग्रस्त प्रान्तों को आर्थिक सहायता दें ताकि प्रान्तीय सरकारें गरीब लोगों को सहायता पहुंचा सकें। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बिहार राज्य में एक मधुबनी बांध है। उस बांध के टूटने से उत्तर प्रदेश भी प्रभावित होता है। मैं यह बात निश्चित रूप से जानता हूं कि उस बांध के आस-पास के इरीगेशन विभाग के लोग और खास तौर पर इंजीनियर और अन्य लोग अपना ट्रासफर यहां पर कराने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं। वे चाहते हैं कि वहां पर उनका ट्रांसफर हो जाय क्योंकि जब बाढ़ आती है तो उसकी रोकथाम के लिए लाखों रुपया खर्च किया जाता है। उस खर्च का 50 प्रतिशत भाग इंजीनियरों की जेब में चला जाता है। अभी जैसा हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य ने खबर दी है कि अभी अभी एक घंटे पहले वह बांध टूट गया है। मैं चाहता हूं कि शीघ्र ही इसकी जांच की जानी चाहिए कि यह बांध क्यों टूट गया। फ्लड कण्ट्रोल पर सरकार इतना रुपया खर्च करती है, लेकिन उसका लाभ लोगों को पूरा पूरा नहीं मिल पाता है। इस विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसकी जांच की जानी चाहिए। अन्त में मैं फिर आग्रह करूंगा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों की प्रान्तीय सरकारों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता दी जाय ताकि बाढ़ग्रस्त लोगों को समय पर सहायता पहुंचाई जा सके।

SHRI AJIT KUMAR SHARMA (Assam). Sir, we are discussing a problem which has already become serious throughout the country. The recent floods in Rajasthan desert point to this fact,, and warn the present Government at the Centre to see that unless planned steps are taken to solve this problem of floods, we may face a very serious situation in future.

Now, Sir,, about the northern States, we have already discussed the problem of floods which they have been facing all these years. But, Sir, in the Eastern States, particularly the State of Assam, we have been facing this problem for a very long time and the problem there i$_s$ not only very serious and devastating, but is also of a very different nature from that of the problem faced by the other States. The floods here are not only a long story of annual sorrow, but also a story of permanent distress for the country. This is not a problem of a State alone. But it is a problem whica affects the entire economy of the country and also the economic prospects of the country. Though the negligence that has been there for long years,, the river Brahmaputra which was a river of wealth has been allowed to become a river of sorrow. This river could be utilised not only for controlling the floods but for producing an amount of electricity which could feed half of India. This has been stated and examined by different experts from time to time. But, unfortunately, the Government of India has not taken so far any concrete measure to utilise the wealth contributed by thi$_s$ particular river.

Now,. Sir, if I come to the question of Assam, the flood situation in Assam has become serious particularly since 1950, when there was a great earthquake in that region. And consequent upon that earthquake,, new situation'. arose because of which we have been facing annual floods. There are three floods visiting Assam every year. From May to July is the period when the people on both sides of the Brahmaputra and other tributaries have to continue a life of anxiety and distress and economic loss. In terms of economic loss, the State has been suffering at the rate of Rs. 15 to Rs. 20 crores every year, and sine© 1950 up till now,, according to expert calculations we have lost more than Rs. 1000 crores worth of agricultural goods in addition to tremendous suffering caused to the people. It not only causes suffering but also destroys the will of the people to survive and to ptoduce.

[Shri Ajit Kumar Sharma]

This is a very serious aspeci which has been neglected so far. We have been hearing debates about the responsibility of controlling floods—whether it is the responsibility of the State Govern-.ments or of the Central Government. This is a very peculiar phenomenon operating for the last so many years in our country. Now, for instance, when the floods are not controlled, people suffer and they protest, and when the protest comes then we think that the protest is either provincial or parochial. But when the question of controlling the floods and the responsibility of the Centre comes, then we deny that responsibility. This situation cannot be allowed to go on.

Sir, in 1963, Dr. K. L. Rao was the Minister for Irrigation and Power and he was also an expert in the field. He visited Assam during one of the heaviest floods. He toured the whole area and he admitted and declared also that the nature of floods in Assam was of a very special kind and it needed special treatment and that it also demanded special engineering skill which could be provided, not by the State Government, but by the Centre alone,, and he promised that soon he would do something in this regard. But what we find is that the promises are observed only in breaches. A few years later,, in 1968, the then Prime Minister visited Assam during another very heavy flood, accompanied by Dr. K. L. Rao,, and the Prime Minister promised that permanent measures to control floods in Assam would be taken by the Central Government. But the moment the aeroplane left Assam and it reached Delhi, everything was forgotten. In this matter, some assurances, some promises,, are made, some aerial visits are paid by the Ministers, but the problem is left there. Sir,, in Assam, the State Government has got no resources to take appropriate measure fo$_r$ the control of the floods. *(Interruptions)* Now. the nature of the floods in Assam is that it has got Brphmamvtra as the main source of flood. *(Time Bell rings).* After the 1950 earthquake,, the Brahamputra'$_s$ bed became shallow and after that the floods have become more serious. Along with the problem of floods, there is another important problem associated with it. There is a very heavy influx of people into the State every year and every day. This flood of population coming from outside the State is settling in the riverine areas. The settlement of a large number of people in this area has created further problems. It. has increased the intensity of floods. It has also created a greater problem for the whole State. Now, for controlling floods not only has the Brahamputra to be controlled,, but the influx of population has also to be controlled along with the measures of flood control. *(Time Bell)* There are two things which I want to point out. There is the question of controlling the Brahamputra river and for it the Brahamputra Commission was appointed in 1972. *(Time Bell)* Originally this Commission was to be taken over by the Central Government .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHY AM LAL YADAV): Please conclude.

SHRI AJIT KUMAR SHARMA: But later on it was left to the State Government. Now, although the Commission exists, it is unable to function for want of funds. The Central Government has not taken the responsibility of .the Brahamputra Commission. I urge upon the Minister that immediate steps be taken to take over the Brahamputra Commission which has already been functioning for four or five years. The centre should also take permanent measures to control the floods. The measures by the Central Government are very necessary. Otherwise we will ruin the entire economy of the State. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHY AM LAL YADAV): Mr. Chanana.

SHRI L. R, NAIK (Karnataka): The South must also be given a chance. The subject is not of floods alone. It also concerns the drought-prone areas.

श्री नत्थी सिंह : साउथ और नार्थ का सवाल नहीं है, देश का सवाल है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHY AM LAL YADAV): Your name is on the list. You will get your chance. Please have some patience. Mr. Chanana.

SHRI CHARANJIT CHANANA (Delhi): Sir. I join in the unanimous decision taken by the House that the Government must keep in mind that floods and droughts are not State subjects or Central Government subjects. They are national subjects and they should be treated and taken up at the national level. Secondly, the two terminologies—drought and flood—are in fact obsolete. It just reminds of a similar thing. About 12 or 13 years back, malaria used to spread as an epidemic and we got rid of it by taking quinine. Now,, quinine was only a .short-term measure. It was a treatment only for that particular period in •order to get rid of malaria. But for a perspective medico man or for a perspective planner in the science of medicine, it was essential to kill the mosquitoes. It was the eradication of malaria which helped the country. Unfortunately, it has come up again.

Sir,, both floods and drought are a part of the ₍oncept known as Water Management. If you go and talk to the United Nations people or the people of the advanced world—not that they want to give you a new jargon— they would tell you that these two things are related and they are two aspects of the same problem and that is water management. It is not a coincidence that we brought 6 P.M. both agriculture and irrigation under one Ministry. The one reason for this was that they have to be co-ordinated, and there has to be a national co-ordinated plan for water management in this country. The Five Year Plan which has now started rolling and which should have, therefore,, a longer perspective, had a heading known as the 'Flood Control' at page 140. And the first sentence is, 'the flood control is an important social and economic necessity.' I would say that it is a *sine qua non.* But there is no separate section devoted to drought. I would suggest that the Rolling Plan, should re-do it, and the next document in the Rolling Plan which comes out should have a separate chapter on it. Not only that. Under this Ministry, you should have another Department and it should be Water Management Department. Now,. Sir, I would not quote the instance of Uttar Pradesh and Bihar which are the case studies in the country though the area from where I come does receive floods. But floods or water management is a national problem and it should be viewed like that.

Sir, the second thing, is the resources position. I personally feel that there is no problem about resources. The main thing that the Janata Government of India have to do today is that they have to re-orientate, they have to reschedule, or prepare a schedule, if they do not have one, of priorities. And the top priority for utilisation of the reserves that they have should be according to the slogans raised by them and the first slogan fortunately for the country although it is a repetition of the old one is rural development. If at all you mean to attain that, then my suggestion to you is this. You have a reserve—and part of which was inherited by your Government from the previous Government—of Rs. 4,500 crores of foreign exchange. My suggestion to you is,, for heaven's sake, don't do what you are doing. We read in the newspapers that it is draining. In which direction? It is draining towards the US securities and the [us] commercial banks. For heaven's sake, don't do that. It would be a national crime that you would be indulging in at a time when the country needs the resources. It ig the optimum resource utilisation which is most important. For heaven's sake, don't misutilise that.

Now. Sir. I would draw your attention to what I am saying as the econo-

[Shri Charanjit Chanana]

mics of foreign exchange reserves. I will give an example of Israel. There is a national fund there, and the resources from their people settled all over the world went to their mother-land. They flooded the country with funds and Israel was the first country in the w >rld which took up desalination of water through a solar project. Now, I would say one thing. The Indian sf.ttlers abroad are not only rich in their financial resources but they s re rich in talent also. Now, the first p;.rt would be the financial part of it. I can assure you since I have been associf.teci with the Indian settlers abroad right from the early 1970s that this is a rich potential which is giving you Rs. 150 crore3 per month. If you raise a fund which will be known as the National Water Management Fund, you can get fuiids not only from within but from outside also. There are Indians abroad who can Invest in this.

Sir, I would draw your kind attention to the fact that the Five Year Plan or the next Rolling Plan for the years 1978—83 provides for: No. (1) major and medium irrigation projects; No. (2) minor irrigation projects; and No. (30 flood control. The total comes to Rs. 9,650 crores. By raising Rs. 1800 crores per year, you will have Rs. 9.000 crores i'n five years. This is frc-m the Indian settlers abroad in addition to what you already have, i.e. Rs. 4,500 crores, plus the resources that you have already allocated. I am not going to disturb your original allocation of Rs. 9,650 crores. And this would give you a source-base of more than Rs. 23,000 crores. If you have this much, then you cannot talk of resource starvation at all. You have a very rich base. What is needed is another thing which does not have to be imported. That is there. You have to generate that, and that is the determination to do it. You should be prepared to do one thing and that is translate your slogan of rural development into action. Then, there is the thirj thing which is very important. You claim'paucity of resources. But out of Rs. 94 crores provided for the drought prone areas the utilisation Is' only about 40 per cent. Sixty per cent is not being utilised. I would suggest that the Government Should inquire into the reasons for non-utilisation of this money and find out as to why This is happening. Nearly Rs. 100 crores is the outlay meant for the drought affected! areas. Once you are able to do what I am goivig to suggest to you the problem can be substantially solved. It is not only a question of national grid for water and power. There is something beyond that also- I have talked to the engineers in different parts of the country and they tell me that the problem of regulating the Brahmaputra and other rivers in the Ga'nge-tic plain would require international understanding with Nepal and Bangladesh, Now, you have offered the Farakka barrage in a platter to Bangladesh. Then you also claim that you have generated a very good political environment with the neighbouring countries If that is so, I would like you, in the national interest, to prove that you mean it and the proof would come only if you float the concept of the South-Asia water and energy grid.

I am told by the engineers that in the GaWgetic plain you cannot have a dam to regulate waters. Here, the engineers have told me, the water can be regulated by two methods. The water can be regulated by having underground storage facilities. This is a new concept. The latest evolved by them. We are very fortunate in one thing. This country is very rich as far as technical k'now-how is concerned and we can translate this idea into practice.

I will just take a minute more, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Please come to the conclusions.

SHRI CHARANJIT CHANANA: Yes, Sir. Now, this South-Asia grid, if you actually mean to put it into practice, would give you a very good result. We should see that China

has been doing. We should learn some things from the neighbouring countries. There is no harm in that because the whole world is like a laboratory. We can learn from other people's experience also. In the drought prone areas or in those areas where agricultural operations take place only for two months or three months in a year and for the remaining nine months the manpower resources are available, their planning is to utilise that manpower by giving them some employment. This is what we^can also do fa the drought prone areas or flood affected areas because this is a temporary feature and we can promote plans of employment for these people. Secondly, Sir, once you are able to implement that grid, you would not only generate a very large scale employment potential for the country, you would not only be able to convert the country into a rich prosperous agricultural country, a country of 575 thousand prosperous villages, but you would also do another thing, namely, that you would promote vast tourist areas in this country with excellent navigation channels, once you are able to regulate the water.

So, Sir, my conclusion is that we have all the resources but "what we need is determination and translation of determination hit0 action. If we are able to do that, we can definitely have a rich optimum model of water management in this country. This country has a very rich potential but the only thing that we need is our determination to plan and translate that plan into action,

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO: You want that they should plan their work and then work on their plans. They have not been able to prepare their plans but they are working on them.

श्री शिव चन्द्र झा : उपसभाध्यक्ष महोदय, 18 जुलाई को इस बाढ़ के प्रश्न पर एक कालिंग अटेन्शन नोटिस थी, जो मेरे नाम से और दूसरों के नाम से नोटिस थी । उस वक्त भी यह सवाल उठाया गया था, बाढ़ की समस्या के बारे में । मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया मैंने उस वक्त कहा कि वह सन्तोषजनक नहीं था और उन्होंने गंभीरता से जवाब देने की कोशिश नहीं की । कहने का मतलब यह है कि बाढ़ की समस्या गम्भीर है लेकिन ऐसा देखा जाता है उस गंभीरता को ये महसूस नहीं करते । सरकार की तरफ से महसूस नहीं किया जाता है और रेडियो वाले भी उस गंभीरता से बाढ़ की खबरों का प्रसारण नहीं करते हैं । हर साल मानसून सेशन में इस बात पर बहस चलती है, जैसा कि एक सदस्य ने कहा रिट्युअल के रूप में बहस करते हैं और मंत्री महोदय बना-बनाया जवाब पढ़ देते हैं; बात वहीं खत्म हो जाती है । एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से या राष्ट्रीय पैमाने पर या राष्ट्रीय लेवल पर गंभीरता से इसको हल करने की कोशिश नहीं होती । अब इस पुरानी लम्बी 30 साल की बीमारी पर मैं जाना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसकी गंभीरता को महसूस नहीं किया जा रहा है । बाढ़ फर्स्ट प्राब्लम है । देश में जो बाढ़ से बरबादी होती है, जान-माल की और करोड़ों की बरबादी होती है इसकी जड़ में और बातों के अलावा यह है कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं, बाढ़ कंट्रोल की, वे योजनायें भी कार्यान्वित नहीं हो रही हैं । मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मैं खुद भी बाढ़ का भुक्तभोगी हूं । अभी जो बाढ़ आई है बिहार में, हर साल मैं देखता हूं मेरे आंगन में जिसको कोर्टयार्ड कहते हैं पानी चला जाता है । मधुबनी में जब मैं बाढ़ के वक्त निकलता हूं तो एक लुंगी पहन कर सब कपड़ों को झोली में भर कर आध किलोमीटर पानी में चलता हूं । मधुबनी में इतने पानी में हिलते डुलते मैं फिर घर आता हूं । और यह बाढ़ इसलिए है कि हमारे गांव के सामने जीवट नदी है वह ब्लाक्ड है, इसमें एक नीमा स्कीम 1966 में बनी थी लेकिन वह बनी—सब कुछ है, सब कुछ बन गया—लेकिन वह स्कीम अभी तक कार्यान्वित नहीं हो पायी है । जो बिहार

[श्री शिव चन्द्र झा]

के इस विभाग से संबंधित मंत्री हैं उनसे पूछ लें कि नोमा स्कीम का क्या होगा और कब वह स्कीम कार्यान्वित होगी ? क्योंकि अगर वह स्कीम कार्यान्वित हो जाएगी तो मेरे इलाके में बाढ़ नहीं आएगी । वहां जो बाढ़ आती है वह ओवरफ्लो करने से बाढ़ आती है । बात बहुत आसान है लेकिन मैं देख रहा हूं उस स्कीम को जिसको बढ़ाने में और उसके सिलसिले में दौड़-धूप करने में मेरा हाथ था, हर साल उसको रिवाइज करते रहते हैं कि कास्ट कितना बढ़ा है । ऐसे ही होता रहता है और कार्यान्वित नहीं होता है । *तो यह जो मशीनरी है, निकम्मेपन* की जो बीमारी है, जब तक आप सख्त मुस्तैदी के साथ ख़ात्मा नहीं करते हैं, वार फुटिंग पर काम नहीं करते, तब तक यही समझा जाएगा कि आप इसको सीरियसली नहीं टैक्ल कर रहे हैं ।

दूसरा उदाहरण ले लें उपसभाध्यक्ष महोदय । वेस्टर्न कोसी नहर योजना के बारे में सब लोग जानते हैं । कितना बड़ा उदघाटन हुआ, कितने नेता गए, लेकिन फिर भी वह योजना कहां पर रुकी ? क्यों नहीं वह कार्यान्वित होती है ? मंत्री महोदय मैं आपसे पूछना चाहता हूं : 18 जुलाई को नोटिस आई थी बाढ़ पर, 18 तारीख के बाद आज के दिन जो 16 दिन व्यतीत हो चुके हैं, कितने बाढ़ग्रस्त इलाकों में आप गए हैं, कितना वैयक्तिक संबंध आपने कायम किया है? बिहार के मुख्य मंत्री कर्पूरी ठाकुर ने आपको एस ओ एस दिया—अखबार में आया—कि जल्दी वहां से मदद भेजो और मांग की। मैं स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूं : कौन सी मदद केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को दी ? पटना डूब रहा है, दरभंगा डूब रहा है, सारा नार्थ बिहार डूब रहा है । आपको ख़बर दी जाती है । आपने कौन सा कदम वार फुटिंग पर, ख़ास कर बिहार के लिए, उठाया है ? मैं स्पष्ट शब्दों में यह पूछना चाहता हूं । उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा एक तरह से रिट्युअल फार्म में बात हो जाती है । आयी बात इस कान से और उस कान से चली गयी । इधर से आया तो जवाब दे दिया पढ़ कर । वहां जो आफिसर्स की पलटन जो अंग्रेजी जमाने से आ रही है, वह ब्यूरोक्रेसी की पलटन जिसके पंजे से आप निकल नहीं पा रहे हैं और अपने से देखने की कोशिश नहीं करते हैं : मैं महसूस करता हूं कि बाढ़ की क्या तकलीफ होती है । हमारी आंखों के सामने बाढ़ आती है । मैं भुक्तभोगी हूं । जो दशा उस वक्त होती है उसका मैं वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं देखता हूं कि इस बाढ़ की समस्या *का वार फुटिंग पर मुकाबला नहीं किया जाता* है । पिछले तीस साल तक तो मैं समझ सकता था कि ऐसा क्यों नहीं हुआ । उनकी नीति थी गद्दी पर बने रहने की । उनको बाढ़ की समस्या से कोई मतलब नहीं था, लेकिन अगर हम में त्रुटि हुई और जनता सरकार के यहां स्थापित होने के बाद भी अगर सरकार वार फुटिंग पर बाढ़ के लिए कोई काम नहीं करती है, कोई कदम नहीं उठाती है तो भारत की जनता हमें माफ नहीं करेगी । भारत की जनता ने उनको माफ नहीं किया और भारत की जनता हमको भी माफ नहीं करेगी । भारत की जनता में चेतना है । उसमें जवाब देने की चेतना है इसलिये मैं इस बात को बहुत सीरियसली रख रहा हूं । अभी ब्रह्मपुत्र की बात आयी, गंडक की बात आई, लेकिन मैं उन सब में नहीं जाना चाहता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं सिर्फ सवाल पूछना चाहता हूं कि जो बड़ी बड़ी किताबें हैं उन की बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन मैंने एक सवाल उठाया था कि जिस तरह से फायर ब्रिगेड है, उस का नाम भले ही आप कुछ और दें लेकिन क्या आपके सामने कोई फ्लड ब्रिगेड भी है । क्या आपने इस

तरह का कोई फ्लड ब्रिगेड सेंटर के लेविल पर बनाया है ? क्या कोई बात सोची है उसके बारे में कि जिस में आप बरसात के दो तीन महीने पहले आप अपनी मशीनरी को गियर अप कर लें और वह बाढ़ आने पर काम कर सके । आप देखें कि उन एरियाज में तो नाव तक नहीं बनायी जाती है । जब बाढ़ आने वाली होती है तो पहले से उसके लिये कोई इंतजाम नहीं होता है। यह बात मैं अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूं । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप के पास कोई फ्लड कंट्रोल ब्रिगेड है । अगर नहीं है तो आप सोचें कि किस तरह से आप ऐसा एक दस्ता बना सकते हैं। कैसे आप इसको स्थापित कर सकते हैं । आप देखें कि आपके यहां लोग क्या करते हैं और राज्य सरकारें क्या करती हैं । फौज का बाढ़ को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है । सेना के इस्तेमाल का मतलब है कि आपका जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वह सब निकम्मा हो गया है । हम सब निकम्मे हो गये हैं और इसलिये सेना का इस्तेमाल करना पड़ता है । इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक फ्लड ब्रिगेड बनायें । मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जब तक प्रोजेक्ट्स कार्यान्वित होते हैं तब तक के लिए फ्लड इंश्योरेंस स्कीम चलाया जाय । एक बाढ़ बीमा स्कीम आप चलायें ताकि जहां जान की क्षति होती है, माल की क्षति होती है या घर द्वार की क्षति होती है उसके लिये लोगों को कुछ मुआवजा मिल सके । जो बाढ़ से पीड़ित होते हैं उनकी सहायता के लिए आप बाढ़ बीमा योजना चालू करें । जब आपके ये प्रोजेक्ट्स चालू हो जायेंगे तब तो बहुत से मसले हल हो जायेंगे । लेकिन तब तक के लिये फ्लड इंश्योरेंस स्कीम आप चलायें । और भी बहुत से काम हैं जो आपको करने होंगे । जैसे मधुबनी का बांध टूट गया, उसे आपको देखना चाहिए । उसके लिए आपको चार फुटिंग पर काम करना चाहिए । आप खुद जायें और देखें कि उन बाढ़ के इलाकों में क्या काम हो रहा है और बाढ़ के इलाकों से जहां से सहायता की मांग आयी है उनकी मुस्तैदी से आप मदद करें । राज्य सरकार उसके लिए क्षम्य नहीं है। जितनी बड़ी समस्या है उसको वह अपने साधनों से हल नहीं कर सकती। इसलिये इन बातों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाता हूं ।

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय शिवचन्द्र बाबू की भावना के साथ मैं सहमत हूं और इसमें कोई दो मत नहीं कि बाढ़ की इस समस्या का निदान करने के लिए सरकार सोचती है लेकिन इसको क्रियान्वित करने में सक्षम नहीं हो पाती है । अभी हाल ही में माननीय सदस्यों ने इसकी चर्चा की कि बिहार, यू० पी० और असम की बाढ़ की समस्या के विषय में हमने ऐडिटोरियल पढ़ा कि जब बाढ़ आती है तो सरकार भी जगती है, विधायक भी जगते हैं, अखबार भी जगते हैं लेकिन बाढ़ के चले जाने के बाद वे इसकी तरफ़ मुड़कर भी नहीं देखते हैं । ठीक ही किसी ने कहा कि एक रिचुअल हो गया कि जब बाढ़ आती है तो हम इस सदन में इस समस्या को लेकर अनेक प्रश्न उठाते हैं ।

उपसभाध्यक्ष जी, सचमुच में यह बहुमुखी समस्या है । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पिछली बार भी चार अगस्त को हमने—कागजात देखें—इसकी चर्चा यहां हुई थी और बरनाला साहब ने यह घोषणा सदन में की थी कि एक मास्टर योजना बाढ़ को रोकने के लिए हम तैयार करने जा रहे हैं । लेकिन वह योजना कैसे होगी, क्या होगी, कब होगी उसका प्रारूप हम लोगों के सामने नहीं आया। यह कोई राजनीतिक समस्या नहीं है । बाढ़ से जनता पार्टी ही चिन्तित हो ऐसी बात नहीं है, पूरा जन समुदाय इससे ग्रसित है और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि हम बेचैन हैं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस समस्या के दो पहलू हैं। एक बाढ़ को रोकने की। उस पर माननीय सदस्यों ने बहुत सुझाव दिये हैं। एक ठोस गम्भीर योजना हमें बनानी है और जिस तरह से बाढ़ के समय में आसानी से दोनों हाथों से पैसा बांटते हैं, अगर बाढ़ को रोकने की योजना को कियान्वित करने में अगर उसी धनराशि को देने के लिए हम मुस्तैद हो जायें तो मैं समझता हूं कि कुछ वर्षों में बाढ़ की योजना बन जाएगी और हम लोगों का कल्याण हो जायगा। मैं खासकर उत्तरी बिहार की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे उस क्षेत्र के बहुत से संसद् सदस्यों ने भी आपका ध्यान आकृष्ट किया। सौभाग्य से हमारे मंत्री राम कृपाल सिंह जी भी उसी क्षेत्र से आते हैं। उनके गांव में 20 वर्षों में बाढ़ आ रही है वह बाढ़ग्रस्त एरिया है। वह अपने गांव भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए हमारा एरिया उत्तरी बिहार का जो है उसके 31 जिले पूर्णिया से लेकर गोपालगंज जो कि रामानन्द यादव जी का क्षेत्र है, सारा हमेशा जलमग्न रहता है। इसमें 10–12 नदियां हैं। अभी हाल ही में विधान सभा ने एक जांच समिति गंगा कटाव की बनाई। उसके सदस्य श्री रामानन्द यादव जी थे। उन्होंने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा कि 1958 से गंगा में 80 फीट बालू आ गया है। आज तक 1958 से उसका कटाव नहीं हुआ। यही कारण है कि जमीन का कटाव होता है। जैसा कि माननीय शास्त्री जी ने कहा रेल यातायात की वहां असुविधा हो रही है। सवाल यह है कि समितियां बनती हैं। हमारे सामने भगवती समिति बनी, गोखले समिति बनी और त्रिपाठी समिति बनी। उनकी रिपोर्टें हैं। 1972 में गंगा बोर्ड बना, 1976 में बाढ़ नियंत्रण बोर्ड बना। राष्ट्रीय बोर्ड बना लेकिन उनकी सिफारिशें कार्यान्वित नहीं होती हैं। कितनी ही अच्छी चीजें होती हैं, कितनी ही अच्छी चीजें बनी थीं, उनको हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके ही जिले में पंडित जी जो विरोधी दल के नेता हैं वह जब मुख्य मंत्री थे एक ही टेहरी योजना उन लोगों ने बनाई। लेकिन उनको अभी विश्वास है कि बाढ़ रोकने के लिए इस योजना को कार्यान्वित किया जाए तो गंगा में बाढ़ का सिलसिला नहीं हो। सचमच में बाढ़ जब आती है तब हम चिन्तन करने बैठते हैं। यह बात ठीक है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वह चाहती है कि बाढ़ आये ताकि गवर्नमेंट का जो पैसा डोल आउट होता है उसको हम खर्च करें। हमारे उत्तरी भारत का कैसे विकास होगा? और भी जो हमारी स्कीम्स हैं 1975–76 में बिहार को बाढ़ की आपको जानकारी है कि 182 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। और सच्चिदानन्द जी जनता पार्टी के हैं और जो सिंचाई मंत्री बिहार में हैं उन्होंने भी कल वक्तव्य दिया कि हर साल बाढ़ से 175 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। और 45 करोड़ का हमारा अनाज का नुकसान होता है। जब यह चीज चलती रहेगी तो बाढ़ को कैसे रोका जा सकेगा। ऐसी बात नहीं होनी चाहिये कि सदन में चर्चा हो रही है और मन्त्री महोदय वक्तव्य दे देंगे कि सरकार यह करने जा रही है और रिलीफ की तरफ कोई ध्यान न दिया जाए। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने जो सहायता मांगी है उसे तुरन्त भेजी जाए। मुझे इसका निजी ज्ञान है कि वहां नावों का कमी है। सीतामढ़ी में एक ऐसी घटना हुई है, राज्य मन्त्री डा० रामदुलाल सिंह जी भी जानते हैं कि वहां पर एक नवल किशोर के परिवार की मत्यु मकान के गिरने से हो गई। उसमें 9 सदस्य थे। इस प्रकार 32–40 लोग मर चुके हैं। कुछ शरणार्थी लोग भी गये थे वे भी वहां वह गये। इस प्रकार वहां दुर्दशा हो रही है। बचाव का जो कार्यक्रम चल रहा है मैं समझता हूं कि वह भी अच्छी तरह से नहीं चल रहा है। कल और परसों वहां की विधान सभा में इस बारे में काफी शोर गुल हुआ।

आप इसे राजनीतिक उद्देश्य से न लीजिए। आप वहां जाकर लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए जो राहत कार्य वहां उचित समझें, दीजिए। नावों की व्यवस्था ठीक नहीं है। रिलीफ आपरेशन ठीक से नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि तत्काल योजना के ऊपर समय न लगा कर, कैसे बाढ़ को रोका जाए इस पर समय न लगा कर, क्योंकि बाढ़ तो आ ही चुकी है, जब चोर आ गया तो उससे कैसे बचा जाए इस पर समय लगाना व्यर्थ होता है, इसलिये इमीडियेट रिलीफ के बारे में समय लगायें। मैं राज्य मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से चाहूंगा कि रिलीफ आपरेशन जो बिहार में चल रहा है और बिहार सरकार की जो डिमान्ड्स हैं उनको मुहैय्या करें। मैं यह भी चाहूंगा कि वह खुद भी जाकर वहां देखें कि किस तरह से रिलीफ आपरेशन हो रहा है। एक्चुअली लोगों को रिलीफ कार्य से रिलीफ मिल रहा है या नहीं इस चीज को जाकर देखें।

अन्त में, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने समय दिया। मैं चाहूंगा कि इसकी गम्भीरता को देख कर राज्य मन्त्री महोदय हमारे बिहार राज्य के राहत कार्य में दिलचस्पी लें। जब यह समाप्त हो जाए तब सब दल के लोग, हम भी और दूसरे लोग भी बैठ कर इस बात पर विचार करें कि फ्लड कैसे रोका जाए। छोटी-छोटी समस्याएं होती हैं उनको हम आपके सामने रख सकते हैं। हमारे शास्त्री जी ने मानसी के बारे में कहा था। उन्होंने यह भी बताया कि लोगों ने उस बात को नहीं माना इसलिये लाखों रुपये बेकार हो गये। हर साल काफी रुपया खर्च होता है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि यह समस्या आपकी समस्या नहीं है इस देश की समस्या है, सबकी समस्या है। इसको हल करना बहुत आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अपने असम, उत्तर प्रदेश, बिहार में अतिवृष्टि और बाढ़ की विनाशलीला का विवरण सदस्यों से सुना मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान राजस्थान की ओर भी खींचना चाहता हूं।

श्री सीताराम केसरी (बिहार) : वहां भी बाढ़ आ गई है क्या ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : असल बात तो यह है, विचित्र बात यह है कि जहां बाढ़ आती है वहां उसका लाभ नहीं मिलता। राजस्थान में अतिवृष्टि के कारण काफी नुकसान होता है और उसका लाभ बाढ़ के कारण आप लोगों को मिल जाता है, राजस्थान को नहीं मिलता। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि केन्द्रीय सरकार की जो टीम जांच करने के लिये वहां जाती है वह अतिवृष्टि को बाढ़ नहीं मानती और राजस्थान सरकार को केन्द्रीय सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिये वह प्रायः नहीं मिलती। उसे एक साधारण अतिवृष्टि कह कर समाप्त कर दिया जाता है।

मान्यवर, राजस्थान में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण 63 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। लगभग 50 हजार मकान ध्वस्त हो चुके हैं। उनमें से लगभग 10 परसेंट बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। हजारों आदमी बेघरबार हो गये हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा बुरा परिणाम इस अतिवृष्टि का होता है वह राजस्थान की फसल पर होता है। राजस्थान में, जैसा कि आपको ज्ञात है बाजरा की फसल होती है, मूंग की फसल होती है, ज्वार की फसल होती है। ये तीनों ही वस्तुएं ऐसी हैं कि जिसमें सामान्य रूप से वर्षा न हो, धूप और पानी उनको न मिले तो फसल नहीं होती है। बाजरे की खेती में स्थिति यह होती है कि अगर अधिक वर्षा हो जाय तो वह बिल्कुल पैदा नहीं होता है। यह कैसी विचित्र बात है कि राजस्थान के लोग अब तक पीने के पानी के लिए तरसते रहे हैं और आपने यह भी सुना होगा कि कुछ वर्ष पहले तो राजस्थान में कुछ इलाकों में सात वर्ष

[श्री हरिशंकर भाभड़ा]

तक वर्षा नहीं हुई। सात वर्ष तक वहां के लोगों ने बादल नहीं देखे। सात वर्ष के लड़के को यह पता नहीं था कि बादल क्या होते हैं। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। पिछले चार साल से वहां पर अतिवृष्टि का प्रकोप छा गया है। अगर किसान आकाश में बादल देखते हैं तो वे घबरा जाते हैं क्योंकि बाढ़ में उनके मकान बह जाते हैं और फसलें पानी में डूब जाती हैं। इतना ही नहीं इस अतिवर्षा के कारण कई ऐसे जन्तु पैदा हो गये हैं जो बहुत ही भयंकर हैं। ये जन्तु टिड्डियों से भी अधिक भयंकर हैं। उनको मारने में कोई भी दवा काम नहीं करती है। किसानों की खेती इन जन्तुओं द्वारा नष्ट हो रही है। अगर आप वहां जायं तो आपको ये जन्तु सड़कों पर मरे पड़े मिलेंगे। इस जन्तु को वहां पर कातरा कहा जाता है। इसकी विशेषता यह होती है कि यह पत्तियां खाता जाता है और पीछे से उसको निकालता जाता है। इसको इन पत्तियों का कंज्यूम करने की जरूरत नहीं होती है। यह कातरा नामक जन्तु इस साल नागौर, चूरू आदि जिलों में बहुत ज्यादा पैदा हुआ है। इसके कारण वहां पर गवार और मूंग की खेती बिल्कुल नहीं हो पाई है। इसी प्रकार से एक दूसरा जन्तु भी इस अतिवृष्टि के कारण पैदा हो गया है। इसको गोजा के नाम से पुकारा जाता है। यह जमीन में एक फीट नीचे रहता है और पौधों की जड़ों को काट कर खा जाता है। इस प्रकार से इस अतिवृष्टि के कारण सारे राजस्थान में विनाश लीला हो रही है। यह ठीक है कि राजस्थान सरकार की जितनी क्षमता है उस हिसाब से वह लोगों की मदद करने की कोशिश करती है। चूरू जिले में राजस्थान सरकार ने 10 लाख रुपयों की मदद दी है। अकेले चूरू जिले में ही 25 हजार मकान क्षतिग्रस्त हो गये और लगभग 10 हजार मकान पूर्णतः नष्ट हो गये। सुजानगढ़ में करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हो गई। आज राजस्थान में यह स्थिति पैदा हो गई है कि पहले जहां पीने को भी पानी नहीं मिलता था आज वहां पर मुहल्ले के मुहल्ले पानी में डूबे हुए हैं। सुजानगढ़ में मकान की सेफ्टी का कोई प्रबन्ध नहीं है। छः या सात फिट जमीन खोदने पर पानी निकल आता है। सारा शहर पानी में डूब रहा है। राजस्थान सरकार के पास इतने पम्प नहीं हैं कि वह इस पानी को बाहर निकाल सके। विचित्र बात तो यह है कि रेगिस्तान में जो शहर बसे होते हैं वे आम तौर पर टीलों के बीच में बसे होते हैं। अतिवृष्टि के कारण जब उनमें पानी भर जाता है तो पानी को निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं रहता है। राजस्थान में पहले 5 इंच से लेकर 12 इंच तक वर्षा हुआ करती थी लेकिन पिछले चार साल से 30 से लेकर 60 इंच तक वर्षा हो रही है। राजस्थान की जमीन बालू वाली है। वह अधिक पानी को अपने अन्दर नहीं रख सकती है। इसलिए बाढ़ के कारण और अतिवृष्टि के कारण अनेक कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। राजस्थान के लोग भूख सहन कर सकते हैं क्योंकि वे लोग भूख सहन करते आए हैं। लेकिन वे लोग इस अतिवृष्टि की विभीषिका से बहुत त्रस्त हैं। इसमें उनके मकान भी नहीं रहते हैं और फसल भी नष्ट हो जाती है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस समस्या को बहुत गम्भीरतापूर्वक हाथ में लें और इसको हल करने के लिए कुछ काम करें। सरकारी मशीनरी तो पिछले 30 सालों से इसी प्रकार से चलती रही है। उसके भरोसे पर काम नहीं किया जा सकता है। आप अधिक से अधिक सहायता राज्य सरकारों को दें। हमारी राजस्थान की सरकार पिछले एक साल से काफी काम कर रही है। इसलिए राजस्थान सरकार को अधिक सहायता दी जानी चाहिए। जब तक आप इस समस्या को हल करने के लिये कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बनाएंगे तब तक यह बाढ़ की समस्या हल नहीं हो सकती है। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस बाढ़ की समस्या की ओर सबसे अधिक ध्यान देने

को कृपा करें । इतना कह कर मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

SHRI L. R. NAIK: Mr. Vice-Chairman, however odd it may look to this House, I rise to invite the floods -from the north to the south's drought-prone areas. I have heard with rapt attention what all my honourable friends from the north have said about the havoc caused every year by the floods. I have also heard the loss caused to property and cattle. No doubt, it is an enormous loss. And one of my friends has even gone to the length of saying that the loss so far caused goes beyond Rs. 10,000 crores. This is an enormous loss. But if we were to view the problems of our country as a whole, you would come to know that loss of the same magnitude is also to be found in the south as a result of famine and scarcity and drought every year. On the one side you get floods in the north to an enormous extent arid on the other side you have areas ifi the south which are chronically drought-prone. The result js that there is a huge loss being caused to the nation. So this is a problem which has to Be tackled on a national basis. As my friends have rightly said, there must be a national policy. Just as we have a national policy for forests, for population, etc., we should also have a national policy for flood control and eradication of drought aud famine. Unless that is thought of, it is impossible for our nation to prevent occurrence of such a havoc every year. Therefore, I urge upon the Government through you, Sir, that it is high time that we take steps to see that the Ganga is joined with the Cauvery in the south. Already there is a scheme for it, and the Dasturs have given a project report which, I understand, envisages an expenditure of crores and crores of rupees. But looking to the nature of the loss that is caused every year, this expenditure is nothing. And the project, I understand was sent to the World Bank and the World Bank has given a feasibility report, and the feasibility indicates that it is quite possible to join the Ganga with the Cauvery. For this purpose an all-out effort must be made in the country. No weak-kneed policy will serve the purpose. Our Prime Minister has told us about peaceful nuclear explosions, blasts and all that. What more peaceful purpose could there"be th*n joining the Ganga with the Cauvery? All efforts must be made, our science must be made use of the services of our scientists must be made use of, to see that the floods that create havoc in the 'north are brought down to the south. The rivers in the north must be tamed in that way. Very recently I had an occasion to visit the Tennessee Valley project in America. I was struck by the efforts man has made there to control the floods and how he has harnessed the river for the best purposes possible. Once it was the valley of sorrow, and today it is the valley of joy. It ca*i even be called the valley of gold. I have also recently visited the Dambdar Valley Project in our country. It is a marvellous job, no doubt. But it is no use speaking about what is behind it. Corruption is there everywhere. What is necessary is that some such project must have to be planned, must have to be executed, on a national basis. I therefore, urge upon the honourable Minister that It is high time the Government thought of having a national policy not only to control the havoc of the floods but also to see that the rigours of famine and scarcity are minimised.

I could speak at lengtH on the subject, but I know his patience is tired now. My patience was also tired. For this purpose, it may not be possible for me to go into details or figures to justify the advocacy of the point that I am making. However, I would like to urge upon the hon. Minister to see that it is high time that a national policy, both to control the floods and also to meet the scarcity conditions, is evolved by him.

With these few words, Sir, I have done.

श्री नत्थी सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री भीष्म नारायण सिंह और दूसरे साथियों का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बाढ़ की तरफ ध्यान दिलाया है और नियम 176 के अधीन दो घंटे की चर्चा उठाई है। लेकिन मुझे एक शिकायत भी है और शिकायत इस लिए है कि अभी केसरी साहब कह रहे थे कि क्या राजस्थान में भी बाढ़ आती है। या तो उनको इस बात का पता नहीं होगा लेकिन उन्होंने कहा था कि राजस्थान में बाढ़ है। राजस्थान का नाम इसलिए नहीं था। उसका नतीजा यह हुआ कि इसका कितना नुकसान हम को भोगना पड़ा। हम राजस्थान वाले जितने सदस्य हैं उनमें से अधिकांश ने काल अटेंशन नोटिस दिया। सभापति महोदय ने यह कह कर टाल दिया कि पहले बाढ़ पर काल अटेंशन आ गया है। परन्तु उसमें भी राजस्थान का नाम नहीं था। तो हमें सिर्फ विशेष उल्लेख करने का मौका दिया गया। उसके बाद नतीजा यह हुआ कि हमारी पार्टी ने भी चूंकि इसमें राजस्थान का नाम नहीं है सबसे पीछे मौका दिया कि आप राजस्थान वाले सबसे पीछे बोलेंगे। हम कहना चाहते हैं अखबार वाले चले जाते हैं, रेडियो वाले चले जाते हैं इसलिए राजस्थान का जिक्र कहीं नहीं होगा। मुझे एक डर लग रहा है माननीय मन्त्री जी यह कह कर न टाल दें कि राजस्थान का नाम नोटिस में नहीं था इसलिए राजस्थान की बाढ़ के विषय में वे कुछ कहने के लिए तैयार होकर नहीं आए। उपसभाध्यक्ष महोदय जिस दिन 27 तारीख को मैंने राजस्थान में बाढ़ का विशेष उल्लेख किया था उस दिन 50 आदमी मरे थे और अब 70 मर चुके हैं। उस दिन 50 हजार मकान नष्ट हुए थे और आज एक लाख हो चुके हैं। उस दिन ढाई करोड़ रुपये की फसल नष्ट हुई थी और अब साढ़े तीन करोड़ रुपये की नष्ट हो चुकी है। राजस्थान में यह हाल है। राजस्थान के रेगिस्तानी जिले चाहे नागोर हो, सीकर हो, झुंझुनु हो, चुरू हो या गंगानगर हो, सबमें बाढ़ है। बाड़मेर और जैसलमेर जिले में तो बाढ़ को विभीषिका है हो वहां पर लोगों के पास रहने को मकान नहीं है। अलवर और भरतपुर जिलों में आए साल बाढ़ आती है। माननीय सदस्यों को ज्ञान नहीं होगा कि भरतपुर और अलवर में हर साल बाढ़ आती है लेकिन मन्त्री जी को पता है कि पिछले साल उनके द्वारा एक अध्ययन दल भरतपुर में गया था और पांच करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ था और यह कहा गया था कि 30 जून तक कोई स्थायी समाधान निकल आएगा। लेकिन बाणगंगा और रामगढ़ से पानी आया यह पानी 36000 क्युसक था जिससे गांव पानी से भरे हुए थे।

भरतपुर जिले में आज फिर पानी भर गया है और बाढ़ का शिकार है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। जो 30 जून की सीमा थी वह समाप्त हो गई है काम क्यों नहीं हुआ? सिवाय इसके कि मशीनरी खरीदने के और कोई काम नहीं हुआ। क्यों इस तरह से निरीहता के साथ लोगों से बर्ताव किया जाता है?

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह कहा गया है कि बाढ़ का स्थायी समाधान किया जाए। आप भी बाढ़ के समाधान की बात कहते हैं। मैं यह चाहता हूं कि जल संसाधनों को राष्ट्रीय साधन माना जाए और भी कई बातें कहीं गई हैं लेकिन सारी की सारी बातें वहीं खड़ी रह जाती हैं। इसका क्या कारण है? मुख्य कारण यह है कि यह कहा गया है कि हम कृषि की ओर भारी ध्यान दे रहे हैं सारे फण्ड्ज को कृषि के विस्तार में लगा देंगे लेकिन आप देखें कि हमारा नजरिया क्या है? अगर कोई वायुयान में मरेगा तो मुआवजा एक लाख रुपये और ट्रेन एक्सीडेंट में मरेगा तो मुआवजा 50 हजार रुपये लेकिन जो बाढ़ से मरेगा उसके लिए क्या है? आपकी कोई स्कीम नहीं है। हमारे चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है कि बाढ़ से मरने वाले को एक हजार रुपया दिया जाए। बाढ़ से जो मरता है एक तो वह खुद मरता है दूसरा उसका घर नष्ट होता है, उसकी फसल नष्ट होती है। लेकिन जो एक्सीडेंट में मरता है उसकी जान जाती है। उसका घर बच जाता है फसल खड़ी रह

जाती है जायदाद रह जाती है। लेकिन बाढ़ से मरने वाले का तो पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। हमारा नजरिया यह है कि मर गया कीड़ा मकोड़ा है एक हजार रुपया देकर बहला देंगे। घर टूट गया तो 100 रुपया या 300 रुपया देंगे। अगर घर कच्चा होगा तो 100 रुपया अगर पक्का होगा तो 300 रुपया दे देंगे। यह नजरिया जब तक नहीं बदलेगा तब तक बाढ़ की समस्या का कोई कारगर हल नहीं निकल सकता।

आज मुझे दुख है, अफसोस है इस बात का कि यह घोषणा करने के बाद इस बात के लिए वचनबद्ध होने के बाद, गांव के गिरे हुए पीड़ित किसानों को हम आगे लायेंगे, इसके बाद भी आज हमारा नजरिया वही है। जो 30 साल से सरकार का चला आ रहा था। उसमें कोई खास बात बाढ़ के मामले में नहीं हम पाते हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे खुद इस बात के पोषक रहे हैं, हिमायती रहे हैं किसानों के बारे में, बाढ़ से पीड़ित होने वाले गरीब लोगों के बारे में, जो गांवों में विशेषतौर से रहते हैं, नीचे के लोग हैं उनके प्रति सरकार का नजरिया बदले। लेकिन जब आप के हाथ में करने की बात आती है, तब आपका नजरिया क्यों अवरुद्ध हो जाता है और यह हो जाता है। यह हमारी सब से बड़ी कमजोरी है इसलिए मेरी आपसे मांग है कि जहां आप फौजी सहायता दें, लोगों को बसा सकें जिनके घर खराब हो गये हैं बाढ़ से, राहत देने का काम भारत सरकार और दूसरी राज्य सरकारें बड़े स्तर पर करें वहां निश्चित रूप से आपको यह पालिसी डिसीजन करना चाहिए कि बाढ़ से मरने वाले लोगों के लिए मुआवजा दिया जायगा, उनको फसलों का, उनका और उनके घरों का मुआवजा दिया जायेगा केवल उनको निरीह की तरह नहीं छोड़ दिया जायगा। आप फसल बीमा योजना क्यों नहीं लागू करते हैं इतने दिन से हम कह रहे हैं, आप कहते हैं कि अ[illegible] दस ह[illegible] बिज दा कभी कुछ और बिज दिया। हर साल हम कहते आ रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है। किसान नष्ट होता चला जायगा उसका उसको कोई राहत नहीं मिलती है क्योंकि वह गरीब आदमी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिए।

इसके साथ ही साथ दूसरी बात मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह करना चाहता हूं कि राजस्थान में तीन तरह से बाढ़ से लोग पीड़ित हैं। एक तो जो अति वृष्टि के द्वारा जो बाढ़ बनती है उससे, दूसरा हमारी जो बरसाती नदियां हैं जब जोर से बरसात आती है तो उसमें उफान आ जाता है, उससे और तीसरा अन्तर्राज्यीय कारणों से। अभी तो हम जो राजस्थान के लोग हैं, वह जो राजस्थान में बाढ़ आई हुई है उससे पीड़ित हैं, वह पानी से आई है परन्तु अब हमको डर लग रहा है कि यमुना में भी उफान आ गया है और यमुना में उफान आ गया तो हरियाणा पानी छोड़ेगा। क्योंकि रेगुलेटर उनके हाथ में है और यू० पी० वालों के जो कि उप-सभाध्यक्ष महोदय आपका और मंत्री जी का प्रान्त है, उनके हाथ में है। रेगुलेटर से वे पानी ले जाते हैं और बीच में पिछले साल से हमारे यहां 50 हजार बीघा जमीन, पिछले साल से लेकर अब तक पानी के नीचे है उस पर एक दाना भी नहीं बोया गया और उस जमीन में फिर पानी भरेगा और हम निरीह की तरह रह जायेंगे। यह तो जंगल लाल है इसलिए मैं कहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का फैसला करना चाहिए, चाहे वह गोवर्धन ड्रेन हो, जीना हो, काम हो इन सब पर कन्ट्रोल होना चाहिए। यह निश्चित रूप से केन्द्र के हाथ में होना चाहिए था इस पानी को मास्टर प्लान जो सारे देश की नदियों का एक ग्रेड बनेगा, जब वह बनेगा तब बनेगा लेकिन इनका तो मास्टर प्लान बना सकते हैं। हमको भरतपुर फीडर पर पानी देते नहीं हैं, हमारा हिस्सा यमुना में तय हुआ है ओखला में उसको आप देते नहीं हैं, चाहे हरियाणा और यू०पी० वालों को

[श्री नत्थी सिंह]

हम पैसा देने जा रहे हैं। इसलिए गुड़गांव कैनाल जो राजस्थान में जाती है उसका पानी हमें नहीं मिलता है । एक तरफ यह हालत है और दूसरी तरफ बाढ़ का पानी जरूर छोड़ा जायेगा। इसी सदन में हमने अनेक बार कहा कि यमुना में हमारा हिस्सा दो तो हमारे कमलापति त्रिपाठी जो उस समय सदन के नेता की हैसियत से बैठते थे, वह कहने लगे कि गंगा के बेसिन में पानी ही नहीं है और आज आप त्राहि त्राहि की बातें करते हैं । यह जो हमारे दृष्टिकोण की कमजोरी है, इस दृष्टिकोण की कमजोरी को बदलना पड़ेगा । अन्तर्राज्यीय जो संकट है उसके लिए आगे आकर इसको हल करना होगा । मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि राजस्थान को आप भूल जाते हैं, पीछे पटक देते हैं, कोई बात नहीं है, हम पीछे पटके जाने के बाद भी इतने ताकतवर हैं कि अपना हक लेकर रहते हैं । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में जो विशेष स्थिति है जिससे लोग पीड़ित हैं एक अतिवृष्टि के कारण, बरसाती नदियों के कारण, जो बरसात में उफान में आती हैं, उसके कारण । इसके लिए आपने जो पैसे दिये उसको अफसरों ने लगाया नहीं। उनकी अपने जांच नहीं की कि क्यों नहीं लगाया ? इसके अलावा तीसरा अन्तर्राज्यीय जल के ऊपर कोई भी केन्द्र का कन्ट्रोल न होने के कारण, राहत न मिलने के कारण। पानी तो हमको मिला नहीं, सिंचाई के लिये नहीं मिला लेकिन बाढ़ के लिये मिल गया । तो मैं चाहता हूं कि इन सब समस्याओं पर आप ध्यान दें तथा अन्य प्रदेशों के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार तथा दूसरे जैसे आसाम है जिसमें बाढ़ की समस्या है उनको आप सहायता दें लेकिन उनके साथ-साथ राजस्थान को भी दें । लेकिन मूलभूत जो बात है, राष्ट्रीय समस्या है तो आप को इस राष्ट्रीय समस्या और बाढ़ के पीड़ित आदमियों के प्रति दृष्टिकोण का परिवर्तन भी निश्चित रूप से करना चाहिए तभी असली समस्या का समाधान होगा । आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद ।

SHRI K. K. MADHAVAN (Kerala): Sir, I rise to apeak lest the Central Government should forget the case of Kerala. As is usual, Kerala is the first State to be blessed by the southwest monsoon and Kerala is the first —and sometimes the worst—to be affected by the monsoon. And the monsoon travels to the north gradually and there is a passage of time, a time-lag of something like one-and-a-half months from the time it arrives in Kerala and the "time it arrives in UP. That time-lag is there. And because of this time-lag, what happened in Kerala one-and-a-half months back or one month back becomes forgotten by the time the ravages in U.P., Bihar, Assam and all these places crop up in this House. So, my request is that the case of Kerala should not be forgotten. As a matter of fact, even the Cabinet Minister himself stated that they have certain reports from Kerala that certain parts of Kerala have been hit by the south-west monsoon at its worst. But when I stand here in the Rajya Sabha, I should speak something about places outside Kerala also. My friend, Mr. Goswami, not only very ably presented a very good case for his State but he did it with an all-India perspective. That is a spirit which ought to be emulated by everybody. When I stand here, I do not forget the land of the Brahmaputra and the land of the Ganga. Before going to that, I may mention that there is another problem of Kerala. Keralas coastal belt is as long as the State itself—roughly 400 miles, or at least above 350 miles. That is length of the coastal belt. And at many places in this coastal area, there is sea erosion. Kerala js the worst affected by sea erosion almost every year. *(Time-bell rings)*

Coming to the Ganga and the Brahmaputra, these are supposed to be two holy rivers. The Ganga, according to the epics or the legend or fiction, whatever it may be, is sup-

posed to have been brought to the earth from the heavens by Bhagirath and its weight was so much that Shiva himself had to come t° bear it and hand it down to the earth. That is the story of the origin of Ganga. Jawaharlal Nehnf has very ably, in his own inimitable poetic style, presented the Ganga in all its beauty, grandeur and mischief. That Ganga is a small stream in the winter but it becomes turbulent. It has become turbulent now. That is what we have been speaking about. What about the Brahmaputra, the child of: all-creating Brahma? My friend, the award-winning music director, Bhupen Hazarika, composed himself, sang himself and directed himself a beautiful song about the Brahmaputra: "You have been created by the all-creating Brahma; you have been so sweet and beautiful to this country; but you are the source of all sorts of tears to this country also." That is the tragedy of the holy rivers. Is it not strange, Sir, that such wonderful and beautiful rivers become the sources of all sorts of mischief and tragedy?

I would say, as my friend, Mr. Goswami, has said, a new Bhagirath is required not like the old Bhagirath when nature could not be tamed nor harnessed easily. Today science and technology have made wonderful progress and they are at your command. You can utilise them to the best use of the society. As my friend, Mr. Naik, has said, if you can link the Ganga with the Cauvery, it is not a question of linking the north and the south, but it is linking north India with south India with a new life, with new arteries. Not only that. If a comprehensive scheme is drawn up and effectively implemented, the water that is being wasted into both the Arabian Sea and in the Bay of Bengal, can best be utilised for the future prosperity of this country and no new Bhagirath is required—if only science and technology are usefully utilised. Thank you.

श्री भान प्रताप सिंह : श्रीमन, अपने देश में बाढ़ की समस्या एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग सभी माननीय सदस्यों ने इस समस्या को एक राष्ट्रीय रूप में ही रखा है। इस आज की चर्चा का कोई लाभ दूसरा निकले या न निकले लेकिन इतना लाभ तो निकलता ही है कि कम से कम मेरे मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ा है कि अपना देश कितना विशाल है और इसकी समस्यायें कितनी बड़ी हैं ? हम उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग सोचते हैं कि सारी मुसीबत हमारे ऊपर है जब कि राजस्थान, असम और केरल, सभी जगहों में ये समस्या है। पिछले साल हमारे सामने आंध्र देश का साइक्लोन जो आया उसका उदाहरण है। मैं मानता हूं, विज्ञान आज बहुत विकसित हो चुका है। अगर हमारा मनोबल ऊंचा हो, हमारे इरादे पूछे हों, तो बहुत सी समस्याओं का समाधान भी हो सकता है लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ये दैवी विपत्तियां हैं, इनसे पूरी तरह से छुटकारा मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। अच्छे से अच्छा प्रबन्ध होगा और धनी से धनी देश में भी दैवी विपत्तियां आती हैं। हम उनको कम करने की कोशिश कर सकते हैं मगर पूर्णतया उनका निराकरण नहीं कर सकते। 1975 के साल में मैं थोड़े दिनों के लिए अमरीका गया था। बड़ा धनवान देश है और वहां बाढ़ की रोकथाम के लिए जो प्रबन्ध है उसकी भी सारे संसार में सराहना होती है। परन्तु मैं जहां ठहरा हुआ था उससे थोड़ी दूरी पर ही बाढ़ आयी और उसमें सैकड़ों मोटरें और मकान बह गए। यह कोई हमारे देश के ऊपर प्रकोप नहीं है। इस प्रकार के प्रकोप सभी देशों पर आया करते हैं।

श्रीमन्, मैं आंकड़े उपस्थित नहीं करूंगा न मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि जो यह बाढ़ की विभीषिका इस वर्ष आई है, और पहले भी आती रही है, उसको किसी तरह से

[श्री भानु प्रताप सिंह]

कम करके, घटा कर रखने का मैं प्रयत्न नहीं करूंगा और इसका कारण यह है कि जो मुसीबत आती है, जो वहां के रहने वालों पर, जो वहां के जानवरों पर मुसीबत आती है। उसका चित्रण आंकड़ों से नहीं किया जा सकता। मैं स्वयं ऐसे क्षेत्र का निवासी हूं जहां बाढ़ आती है और मैं गया भी था वहां 22 और 23 तारीख को और जो दृश्य मैंने देखा है उसके बाद मुझे कोई यह आवश्यकता नहीं रहती है कि मैं आप लोगों द्वारा कही हुई बात को निराधार समझूं। फसलों को क्षति हुई है। आज भी जब आधी वर्षा बाकी है तो लाखों लोग बेघरबार हो गए हैं।

7 P.M.

कोई उनके ऊपर छत न होने के कारण बहुतों को इस बरसात के दिन में भी भीगना पड़ता है। जानवरों के पास कोई चारा नहीं है। उनकी दुर्दशा मनुष्यों से भी अधिक दयनीय है। यह सब बातें हैं और इस बात की शिकायत की गई कि मंत्रिगण नहीं जाते हैं। यदि आप मेरी गिनती मंत्रियों में करें तो मैं कहता हूं कि मैंने सब से पहले यह अवसर लिया, वहां जाने का और यदि लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाही न चलती होती तो मेरा मन तो वहीं है मैं जानता हूं कि वहां क्या बीत रही है। बहुत अच्छा होता यदि एक सप्ताह या दस दिन के लिए इन सदनों को स्थगित कर दिया जाता और हम सब वहां चल कर काम कर सकते। आज केवल दस मिनट के लिये पीछे रहने पर तमाम सदन का रोषभाजन मुझे बनना पड़ा। यदि मैं बिलकुल गैर-हाजिर हो जाऊं तो फिर आप पता नहीं कितने नाराज होंगे। तो आज यह प्रश्न नहीं है कि कोई जाना चाहता है या नहीं। कठिनाई है कि सदन चल रहा है। हमारे जो दूसरे मंत्री जी हैं वह फूड ऐंड एग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन का जो एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है उसकी बैठक में गए हुए हैं। वह भी एक आवश्यक कार्य है।

श्रीमन्, यद्यपि जल और जल से सिंचाई और बाढ़ यह अपने संविधान के अनुसार राज्य के विषय हैं, लेकिन हम इसको ऐसा नहीं मानते हैं कि केवल राज्य सरकारें ही इसके लिये जिम्मेदार हैं। वही इसके लिए सब कुछ कर सकती हैं। हम सब जो कुछ संभव हो करने के लिये तत्पर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बाढ़ का सारा काम उन पर छोड़ रखा है। गंगा बेसिन में बाढ़ के लिये एक बोर्ड बना है। ब्रह्मपुत्र के लिए भी बना है। एक बिल भी बन कर तैयार है ब्रह्मपुत्र के लिये परन्तु जब तक संविधान है हमें उसको मान कर ही चलना पड़ेगा। जो प्रक्रियायें निश्चित हैं, निर्धारित हैं उनके अनुसार ही चलना पड़ेगा। आज कोई भी योजना बनती है तो राज्य सरकारों से हम को उसके बारे में पूछताछ करनी पड़ती है। आप भले ही यहां कह दें कि केन्द्रीय सरकार को सारे अधिकार लेकर एक समन्वित योजना को चालू करना चाहिए परन्तु राज्य सरकारें अपने अधिकारों को आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। चर्चा की गयी कि कुछ क्षेत्र हैं दक्षिण भारत में जहां पानी बहुत नीचे चला गया है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। उन को अगर मोड़ा जाये तो उन क्षेत्रों का उद्धार हो सकता है। हम चाहते हैं और प्रयत्न कर रहे हैं दोनों सरकारों के बीच, लेकिन उसमें अभी सफलता नहीं मिली है। इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने मन से यह बात निकाल दें कि हम लोग किसी प्रकार से उदासीन हैं। उदासीनता का कोई प्रश्न नहीं उठता। एक माननीय सदस्य ने कहा कि सारी जानकारी है, कमी सिर्फ ध्यान देने की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी पीड़ा हमारे ऊपर है और इसका सब से बड़ा सबूत यह है कि पिछले 30 सालों के अन्दर बाढ़ नियंत्रण पर केवल 633 करोड़ रुपया खर्च किया गया जब कि हमारी सरकार ने अगले 5 सालों में उससे अधिक 680

करोड़ रुपया खर्च करने का फैसला इसके लिये किया है ।

ऐसा भी नहीं है कि बाढ़ नियंत्रण के लिये अब तक कुछ न किया गया हो । हमारे अनुमान के अनुसार देश में 25 मिलियन हेक्टर्स भूमि ऐसी है जिसमें बाढ़ आने की संभावना रहती है । उसमें 9.34 मिलियन हेक्टेयर में बाढ़ नियंत्रण का काम पूरा किया जा चुका है । इसका अर्थ यह निकलता है कि जितने क्षेत्र में बाढ़ आ सकती है उसमें लगभग साढ़े 37 फी सदी क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण का कार्य किया गया है और अगले दो वर्षों के अन्दर भी इस साढ़े 37 प्रतिशत को बढ़ा कर 50 प्रतिशत करने का इरादा भी है ।

श्रीमन्, जैसा मैं पहले कह चुका हूं, चाहे जितने उपाय किये जायें फिर भी मुसीबत आ सकती है । उदाहरण के लिये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास कर मेरे जिला गोंडा में बाढ़ आई है उसका मुख्य कारण यह है कि 24 घंटे के अन्दर 26 इंच वर्षा हुई है । कतरमियां घाट का रिकार्ड है 24 घंटे के अन्दर 26 इंच वर्षा हुई । ऐसी दशा में चाहे जितना अच्छा प्रबन्ध होगा वह निष्फल हो जाएगा । राजस्थान को लीजिए जहां 7 वर्ष के बालक ने वर्षा नहीं देखी वहां 50 इंच वर्षा हो जाएगी तो जरूर मुसीबत आ जाएगी । अब जो प्रक्रिया है ऐसी मुसीबत में मदद पहुंचाने की उसके ऊपर भी ध्यान दिलाता हूं । वैसे तो राज्यों के बजट बनाते समय उनके सारे खर्च जोड़ने के बाद कुछ धनराशि अलग से दी जाती है जिसको मार्जिन मनी कहा जाता है । वह मार्जिन मनी केवल ऐसे अवसरों के लिए ही होता है कि जब तक केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता पहुंचे तब तक वह विपत्ति का सामना कर सकें । इसके लिए ही मार्जिन मनी दिया जाता है । राजस्थान में यह मार्जिन मनी 10 करोड़ रुपये से अधिक है और बिहार में भी 4 करोड़ 61 लाख रुपये मार्जिन मनी के रूप में उपलब्ध है । तो तत्काल काम करने के लिए उनके पास धन है और वह कर भी रहे हैं । इसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता वहां की सरकार महसूस करती है कि फिर वह हमको चाहे टेलीफोन से, चाहे टेलेक्स से मैसेज भेज सकती है चाहे पत्र द्वारा कहती है कि आप सेंट्रल टीम भेजिये, हमारे यहां आकर देखिये कि कितनी क्षति हुई है । हम लोग तत्काल उस टीम को भेजते हैं और वह टीम जब देख कर लौट कर आती है, अनुमान लगाकर तो उसके अनुसार फिर उनको ऐडवांस किया जाता है । यद्यपि हमारे माननीय सदस्यों ने इस बात को तो बार-बार कहा कि केन्द्रीय सरकार सहायता नहीं पहुंचा रही है, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश सरकार को छोड़ कर अन्य किसी सरकार ने केन्द्रीय टीम भेजने के लिए हम से नहीं कहा है । मुख्य मन्त्री बिहार ने अखबारों में कोई बयान भले ही दे दिया हो लेकिन जो टेलेक्स मैसेज हमको प्राप्त हुआ है उसमें केवल उन्होंने यह कहा है कि नेपाल से समझौता करके इन बाढ़ों का स्थायी हल निकाला जाए । वह बात जरूरी है । लेकिन आज तो तत्काल राहत की आवश्यकता है । लेकिन जो कुछ मुझे सन्देश प्राप्त हुआ है वह मैं बतला रहा हूं ।

SHRI KALP NATH RAI: This is most important.

श्री भानु प्रताप सिंह : यह बात आपकी सही है ।

SHRI DINESH GOSWAMI: About Assam.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: I am coming to that.

मैं इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह काम केवल बांध बनाने से नहीं होने वाला है । यह काम एक तो अनेक राज्यों की सहमति होनी चाहिए, कुछ अन्तर्राष्ट्रीय सहमति की भी आवश्यकता है । उदाहरण

के लिए बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का बाढ़ नियन्त्रण तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि नेपाल और भारत मिल कर उसके नियन्त्रण की योजना न बनायें ।

श्री कल्प नाथ राय : वह तो एग्रीमेंट हो चुका है ।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं बताने जा रहा हूं आप क्यों परेशान हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव) : पहले इनकी बात सुन लीजिए ।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जब हमारे प्रधान मन्त्री जी काठमांडू गये थे तो वहां सिद्धान्त रूप में सहमति हो गई थी कि दोनों देश मिल कर कुछ योजनाएं बनायेंगे जिसका लाभ नेपाल को भी मिलेगा और भारत को भी मिलेगा । उस फैसले के अनुसार कमेटियां बन गई हैं । दोनों देश के इंजीनियर्स और विशेषज्ञ मिल कर योजनाएं बना रहे हैं । आप इस पर ध्यान दें कि जब किसी राज्य की ही कोई योजना होती है उसके बनने-बनाने में कभी-कभी डेढ़-दो साल लग जाते हैं । जबकि यह तो अन्तर्राष्ट्रीय योजना है, बहुत बड़ी योजना है और जिसमें उनको बिजली भी देनी होगी जो उनकी सरपलस बिजली होगी । कठिनाई यह भी है कि नदियां जो पहाड़ों से उतरती हैं वह काफी लम्बी दूरी तक नेपाल क्षेत्र में होने के बाद भारत के क्षेत्र में प्रवेश करती हैं । एक बार जब वह मैदान में आ गई, नेपाल के अन्दर भी मैदान हैं तो फिर बांध बनाना भी कठिन होता है ।

इसके साथ बाढ़ों पर नियन्त्रण करने के लिये यह भी जरूरी है कि हमारे अपने देश के जो पहाड़ हैं बिल्कुल नंगे हो गये हैं उन पर अफारस्ट्रेशन भी करना होगा । इस दिशा में भी काम किया जा रहा है । जहां तक मेरी जानकारी है नेपाल सरकार को सहायता देने के लिये भारत सरकार तैयार है और यह एक लम्बे अर्से का काम है । अब नेशनल ग्रिड की बात कही गई है ।

श्री कल्पनाथ राय : एक चीज मुझे पूछनी है कि भाल बांध योजना के बारे में नेपाल सरकार और भारत में एग्रीमेंट हो चुका है और पंचेश्वरी के सम्बन्ध में भी एग्रीमेंट हो चुका है, करनाली के संबंध में भी एग्रीमेंट हो चुका है । य तीनों योजनाएं जिन पर एग्रीमेंट हो चुका है मैंने आपसे यह सवाल किया था कि इन तीनों योजनाओं पर 12 सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसके लिये वर्ल्ड बैंक आपकी सरकार, राज्य सरकार और नेपाल की सरकार के डेलीगेशन्स में एग्रीमेंट हो चुका है और अब केवल फाइनेंस का मामला इन्वाल्व है तो क्या आप इसके लिये समयबद्ध और ठोस ढंग से कोई कदम उठायेंगे ? यदि आप ऐसा कर पायेंगे तो हम इन नदियों की बाढ़ों को रोक पायेंगे । यह बात स्पष्ट है Everything is decided. The Central Government finance is involved. Will you do it or not?

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव) : ठीक है बात स्पष्ट हो गई है ।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं निवेदन कर चुका हूं कि केवल सहमति से काम नहीं बनने वाला है । अपने देश में कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है । कोई योजना बनती है तो वर्षों सर्वे होता है कि कहां की मिट्टी ठीक है और कहां इसे बनाना होगा । यह केवल इससे नहीं होता है कि दो देशों की सरकारें सहमत हो गई हैं ।

श्री कल्पनाथ राय : मैं इसके ऊपर क्लैरीफिकेशन देना चाहता हूं दोनों देशों के इंजीनियर्स ने जलकुंडी योजना को समाप्त करके भालू बांध को स्वीकार किया । यह दोनों में एग्रीमेंट हो चुका है ! बांध पर काम करने के सम्बन्ध में everything is finalised

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव) : यह मन्त्री जी बतायेंगे कि फाइनलाइज हो गया है या नहीं ।

श्री भानु प्रताप सिंह: माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि एक स्थान अनुपयुक्त पाया गया।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव) : तीनों स्थानों की क्या स्थिति है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : दूसरे स्थान के लिये मैंने बताया कि दोनों देशों के विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। जिस वक्त उनका सर्वे वर्क खत्म हो जाएगा उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा तो मैं आशा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि धनाभाव के कारण काम नहीं रुकेगा।

लेकिन आप इस बात को समझ लीजिये कि जल्दी में यह काम नहीं हो सकता है। जब दोनों देशों के विशेषज्ञ और दोनों देशों की सरकारें इसको स्वीकार कर लेंगे तो यह काम शुरू हो जाएगा।

श्री कल्पनाथ राय : पंचेश्वरी के बारे में आपने क्या निर्णय लिया है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : अगर आपको नामों से ही सन्तोष हो जाता है तो मैं नाम ले लूंगा। आप जिस पंचेश्वरी और भालु बांध की चर्चा करते हैं उसमें मेरी भी दिलचस्पी है। आप इस बात से सन्तोष करें कि जब बाढ़ आती है तो हमें भी बहुत चिन्ता होती है।

श्री कल्पनाथ राय : मैं माननीय मन्त्री महोदय से स्पेसिफिकली यह जानना चाहता हूं कि शारदा पर जो बांध बनाने की योजना है और जो पंचेश्वरी योजना है उसके सम्बन्ध में हिन्दुस्तान में और नेपाल में कोई एग्रीमेंट हुआ है या नहीं ? जहां तक मुझे जानकारी है इन दोनों सरकारों के बीच में इन योजनाओं के सम्बन्ध में एग्रीमेंट हो चुका है।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव) : इस बारे में मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं। आप पहले उनका जवाब सुन लीजिये।

श्री कल्पनाथ राय : श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि इन दोनों सरकारों के बीच में इस बारे में एग्रीमेन्ट हो चुका है।

I have put **a** specific question to Mr. Minister. Both the countries **have** agreed. The agreement has **taken** place.

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर एग्रीमेंट हो गया है तो ये बांध बन क्यों नहीं रहे हैं ?

श्री कल्प नाथ राय : यह बांध पैसे की कमी के कारण नहीं बन रहा है। क्या भालू बांध के लिए और पंचेश्वरी बांध के लिए सेण्ट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह : अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा सकता है। आश्वासन इतना ही दिया जा सकता है कि हमारा यह भरसक प्रयत्न होगा कि हम इस काम को करें। चूंकि दूसरे देशों से सहयोग करके यह काम हो सकता है, इसलिए इस सम्बन्ध में यही आश्वासन दिया जा सकता है।

श्रीमन्, मधुबनी बांध के बारे में भी चर्चा की गई है। मुझे जो सूचना मिली है उसके अनुसार पहले यह बांध टूट गया था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के और बिहार के इंजीनियरों ने मिल कर इस काम को पूरा कर लिया है।

ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह काम बहुत जल्दी पूरा किया जाएगा। इस ओर हमारा पूरा ध्यान है। इसके बारे में एक बोर्ड बनाने की बात है। उसका बिल बन कर तैयार हो गया है और वह बिल सम्बन्धित राज्य सरकारों को उनके परामर्श के लिए भेज दिया गया है। इस सम्बन्ध में कुछ का उत्तर आ गया है। राज्य सरकारों का अन्तिम निर्णय 17 जुलाई को मिला है। राज्य सरकारों से जो परामर्श मिला है उसको ध्यान में रख कर अगर आवश्यकता हुई तो दूसरा संशोधन करके इस बिल को शीघ्रता से उपस्थित किया जाएगा।

जहां तक केरल का सम्बन्ध है, मैं यह साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं

माना जाना चाहिए कि हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है । फ्लड कण्ट्रोल के विषय में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की सहायता करती है । रुपये को खर्च करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है । केरल के सम्बन्ध में जिस सी इरोजन की चर्चा की गई है, उसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने एक स्कीम स्वीकार की है । उस पर काम हो रहा है । केरल में सी-इरोजन को रोकने के लिए काम शुरू हो गया है ।

SHRI L. R. NAIK: What about the Ganga-Cauvery project?

श्री भानु प्रताप सिंह : आपने गंगा-कावेरी प्रोजेक्ट नेशनल ग्रिड की बात रखी है । आपको यह मालूम ही है कि हमारे प्रधान मन्त्री जी स्वयं इस बात के लिये बहुत उत्सुक हैं । लेकिन इतनी बड़ी योजना एक दम तो चलाई नहीं जा सकती है । आपने स्वयं कहा है कि इसके बारे में परामर्श किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, एफ० ए० ओ० के एक्सपर्टस जो हैं उनको भी कन्सल्ट किया गया है और जितनी दिलचस्पी हमारे प्रधान मन्त्री जी की इस योजना को जल्दी से जल्दी लागू करने की है, इसमें आपको कोई सन्देह नहीं होना चाहिए । इस योजना में बहुत धन लगेगा । यह एक बहुत बड़ी योजना है । शायद संसार में कभी किसी देश ने इतनी बड़ी योजना चलाने की बात भी नहीं सोची है ।

SHRI KALP NATH RAI: What about Hari *bundh?*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHY AM LAL YADAV): Please let him sepak

SHRI LAKSHMANA MAHAPA: - TRO: What about Orissa? Has he for-gotten that?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Let him answer first.

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, अब मैं समाप्त ही कर दूंगा क्योंकि...

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव) : जो सवाल छूट गये हैं, उनका उत्तर दे दीजिये ।

श्री भानु प्रताप सिंह : माननीय सदस्य जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHY AM LAL YADAV): Message from the Lok Sabha.

MESSAGE FROM THE **LOK** SABH£

The Insolvency Laws (Amendment) **Bill, 1918**

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of Rule 120 of the Rules of Procedure and conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 2nd August, 1978, agreed without any amendment to the Insolvency Laws (Am-ednment) Bill, 1978, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 26th April, 1978.'*

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

The House then adjourned at twenty-two minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 3rd August, 1978.

म०प्र०भा०स०मु०मि०रो०न०दि०—एल०एस० III—871 आर०एस०—20-1०-78—570